www.adbhutsamachar.com

अद्भुत समाचार

वर्ष – 15 | अंक–36 | RNI-No.: UPHIN/2011/43806 | लखनऊ, रविवार 04 जनवरी, 2026 प्रातः कालीन संस्करण | (हिन्दी दैनिक) | पृष्ठ–4 | मूल्य 1 रुपया

बुद्ध अवशेष प्रदर्शनी का पीएम मोदी ने किया उद्घाटन

कहा, महात्मा बुद्ध से जुड़े स्थलों, अवशेषों का संरक्षण सरकार की प्राथमिकता

नयी दिल्ली (एजेंसी) प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शनिवार को कहा कि महात्मा बुद्ध से जुड़े जो भी स्थल हैं उनका संरक्षण और विकास करना सरकार की प्राथमिकता है। वह महात्मा बुद्ध से संबंधित अवशेषों की अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनी के यहां आयोजित उद्घाटन समारोह को संबोधित कर रहे थे।

पीएम मोदी ने कहा कि सवा सौ साल के इंतजार के बाद महात्मा बुद्ध से जुड़ी भारतीय धरोहर और विरासत वापस लौटी है और अब भारतीय जनमानस इन पवित्र अवशेषों का दर्शन करके उनका आशीर्वाद पा सकेगा। उनका कहा कि 2026 की शुरुआत में ही यह उनके लिए बहुत प्रेरणादायक अवसर है कि उनके पहले सार्वजनिक कार्यक्रम की शुरूआत भगवान बुद्ध के चरणों से हो रही है। प्रधानमंत्री जिस प्रदर्शनी का उद्घाटन कर रहे थे उन पवित्र अवशेषों में कुछ हड्डियां भी हैं और माना जाता है कि ये भगवान बुद्ध की हड्डियों के अवशेष हैं। ये अवशेष ईसा पूर्व तीसरी शताब्दी के एवं प्राचीनतम माने जाते हैं। इस भव्य प्रदर्शनी में 127 साल बाद पवित्र पिपरहवा की वापस लाई गई वस्तुएं रखी गई हैं। प्रदर्शनी का नाम प्रकाश और कमल जागृत व्यक्ति के अवशेष रखा गया है। मोदी ने समारोह में कहा कि करोड़ों लोगों ने इन पवित्र अवशेषों का दर्शन किए हैं और ये अवशेष पूरी दुनिया को नयी राह दिखाते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत केवल इन अवशेषों का संरक्षक नहीं है बल्कि उनके संदेशों का जीवंत प्रवाह भी है। उन्होंने कहा कि भारत का प्रयास रहता है कि दुनिया में जो स्थल भगवान बुद्ध से जुड़े हैं उनके विकास में भारत सहयोग करे। मोदी ने कहा कि उनका जन्म स्थान भी बौद्ध परंपरा का बड़ा केंद्र रहा है और आज सरकार इन स्थलों का संरक्षण भी कर रही है। अभी जम्मू कश्मीर में बौद्ध काल की परंपरा का पता चला है और उसके संरक्षण का काम भी सरकार कर रही है। श्रावस्ती, सांची, अमरावती, नागार्जुन सागर जैसी जगहों में बौद्ध विरासत का संरक्षण और विकास किया जा रहा है।

उनका कहना था कि महात्मा बुद्ध के संदेश पालि भाषा में थे, इसलिए इसको शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया जा रहा है ताकि इन संदेशों उसके मूल रूप में समझा जा सके। इससे पहले संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कि ये वस्तुएं महात्मा बुद्ध की जीवंत परंपरा से जुड़ी हुई हैं। यह विरासत को बनाए

बरेली में सीएम योगी ने दिवंगत भाजपा विधायक को दी श्रद्धांजलि, परिजनों को बंधाया ढाढ़स

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शनिवार को दिवंगत विधायक प्रोफेसर श्याम बिहारी लाल को श्रद्धांजलि देने बरेली पहुंचे। उन्होंने शहर के शक्तिनगर स्थित आवास पर विधायक को श्रद्धांजलि दी। उनके परिजनों को ढाढ़स बंधाया।

बरेली (एजेंसी) बरेली में दिवंगत विधायक प्रोफेसर डॉ श्याम बिहारी लाल के निधन के बाद दूसरे दिन शनिवार सुबह 11रू 43 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शहर के शक्ति नगर कॉलोनी स्थित उनके आवास पर पहुंचे। मुख्यमंत्री ने दिवंगत विधायक को श्रद्धांजलि दी। उनके परिजनों को ढाढ़स बंधाया। बता दें कि फरीदपुर से भाजपा विधायक प्रोफेसर श्याम बिहारी लाल शुक्रवार को सर्किट हाउस में हुई पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह की मीटिंग में हिस्सा लेने गए थे।बैठक के बाद भोजन के दौरान उनकी अचानक तबीयत खराब हुई थी, फिर करीब घंटेभर बाद ही वह दुनिया को छोड़ गए थे। डॉक्टर ने विधायक की मौत की वजह हृदयाघात बताई है। उनके अचानक निधन से हर वर्ग में शौक है। शनिवार को उनके पार्थिव शरीर के अंतिम दर्शन के लिए मुख्यमंत्री भी पहुंचे। मुख्यमंत्री ने दिवंगत विधायक की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। उनकी पत्नी व बच्चों से मिलकर शोक संवेदनाएं व्यक्त की।

वन राज्यमंत्री डॉ अरुण कुमार सक्सेना ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आए। उन्होंने दिवंगत विधायक को श्रद्धांजलि दी। उनके पूरे परिवार से मिले। मुख्यमंत्री ने विधायक की पत्नी, बेटियों और बेटे से जानकारी ली। सीएम योगी ने विधायक के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया। शोक संतप्त परिजनों को सांत्वना दी। करीब 15 मिनट यहां रुकने के बाद मुख्यमंत्री रवाना हो गए। दिवंगत विधायक के अंतिम दर्शन करने हजारों लोग पहुंचे। शक्ति नगर स्थित आवास से दोपहर करीब 12 बजे उनकी अंतिम यात्रा निकाली गई। फरीदपुर के स्टेशन रोड स्थित श्मशान भूमि पर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। सुरक्षा व्यवस्था के लिए जनपद के तमाम सर्किलों के पुलिस क्षेत्राधिकारी सहित पुलिस फोर्स व पीएसी फरीदपुर में विधायक के कार्यालय से लेकर शमशान भूमि तक तैनात है।

गणतंत्र दिवस परेड 2026: 5 जनवरी से टिकट बिक्री शुरू, सिर्फ 20-100 रुपये में लाइव देखें भव्य आयोजन

नयी दिल्ली (एजेंसी) गणतंत्र दिवस परेड, बीटिंग रिट्रीट की फुल ड्रेस रिहर्सल और बीटिंग रिट्रीट के मुख्य समारोह के टिकटों की बिक्री सोमवार से छह स्थानों पर शुरू हो जायेगी। टिकट रक्षा मंत्रालय की वेबसाइट से भी सीधी खरीदी जा सकती है।टिकटें आधार कार्ड, मतदाता पहचानपत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट और केंद्र तथा राज्य सरकार इत्यादि द्वारा जारी पहचान पत्र जैसे मूल फोटो पहचान पत्र दिखाकर छह स्थानों पर स्थित बूथों और काउंटरों से भी खरीदी जा सकती हैं। टिकट निम्न स्थानों सेना भवन (चार दिवारी के अंदर गेट नंबर 5 के पास), शास्त्री भवन (चारदीवारी के अंदर गेट नंबर 3 के पास), जंतर मंतर (मुख्य द्वार–चारदीवारी के अंदर) संसद भवन (स्वागत कक्ष), राजीव चौक मेट्रो स्टेशन (डी ब्लॉक, गेट नंबर 3 के और 4 के पास) और कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन (कॉन्कोर्स लेवल, गेट नंबर 8 के पास) से पांच जनवरी से 14 जनवरी तक सुबह 10 बजे से दोपहर एक बजे तक और दोपहर दो बजे से शाम 5 बजे तक खरीदे जा सकते हैं।

सीजेआई का बिहार दौराः पटना हाईकोर्ट में बोले सूर्यकांत-

न्याय मशीनों से नहीं, बल्कि सवेदनशील और सक्षम लोगों से मिलता है

पटना (एजेंसी) सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्याधीश (सीजेआई) सूर्यकांत ने शनिवार को कहा कि न्याय मशीनों से नहीं, बल्कि संवेदनशील और सक्षम लोगों से मिलता है और इसी समझ के साथ न्याय व्यवस्था को एक समावेशी, सक्षम और मानवीय न्याय प्रणाली के निर्माण की दिशा में निरंतर आगे बढ़ना होगा। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायधीश आज पटना उच्च न्यायालय परिसर में सात अलग अलग भवनों और संरचनाओं का उद्घाटन करने के बाद न्यायधीशों, वकीलों और उच्च अधिकारियों के एक समूह को सबोधित कर रहे थे। सीजेआई ने कहा कि न्याय मशीनों से नहीं, बल्कि संवेदनशील और सक्षम मनुष्यों से मिलता है और इसी समझ के साथ हमें एक समावेशी, सक्षम और मानवीय न्याय प्रणाली के निर्माण की दिशा में निरंतर आगे बढ़ना होगा। उन्होंने कहा कि पाटलिपुत्र की धरती अनुशासन, तर्क और प्रशासनिक विवेक की प्रतीक रही है। यही वह भूमि है जहाँ से आधुनिक प्रशासन, नैतिकता और लोककल्याण की अवधारणाएँ विकसित हुईं। उन्होंने कहा कि पटना उच्च न्यायालय एक संवैधानिक संस्था के रूप में न केवल संविधान के अंगीकरण का साक्षी रहा है, बल्कि अधिकारों और स्वतंत्रताओं के निरंतर विस्तार की यात्रा का भी महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। सूर्यकांत ने कहा कि सदियों से जो तत्व हमारी संस्थाओं को एक सूत्र में बाँधता है, वह है संस्थागत क्षमता में निवेश–चाहे वह भौतिक संसाधन हों, प्रशासनिक ढाँचा हो या मानव संसाधन। जब हम क्षमता निर्माण की बात करते हैं, तो उसका सीधा संबंध न्याय तक प्रभावी पहुँच से होता है। इसका उद्देश्य ऐसा न्याय तंत्र विकसित करना है जो बढ़ती जनसंख्या, मुकदमों की संख्या और विवादों की जटिलता की चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना कर सके। उन्होंने कहा कि सुदृढ़ और कुशल प्रशासन न्याय प्रणाली की रीढ़ होता है। फाइलों का सुव्यवस्थित संचालन, अभिलेखों का संरक्षण और न्यायिक निर्णयों का प्रभावी प्रबंधन, ये सभी कार्य सामान्य प्रतीत होते हैं, लेकिन इन्हीं से न्यायिक दक्षता सुनिश्चित होती है। जब प्रशासन सुचारु रूप से कार्य करता है, तो न्यायाधीश अपने मूल दायित्वों पर अधिक ध्यान केंद्रित कर पाते हैं और वादकारियों को एक पारदर्शी व भरोसेमंद व्यवस्था का अनुभव होता है।

सीजेआई ने कहा कि आज के समय में प्रौद्योगिकी संस्थागत मजबूती का एक अहम स्तंभ बन चुकी है। डिजिटल, डेटा–आधारित और उपयोगकर्ता–केंद्रित प्रणालियाँ न केवल देरी को कम करती हैं, बल्कि पारदर्शिता बढ़ाती हैं और बुजुर्गों, दिव्यांगजनों तथा दूरदराज क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए न्याय को अधिक सुलभ बनाती हैं। यही वास्तविक अर्थों में न्याय तक पहुँच है। उन्होंने कहा कि यह भी आवश्यक है कि तकनीक समावेशन का माध्यम बने, न कि बहिष्करण का।

दिल्ली लालकिला विस्फोट केस, पटियाला हाउस कोर्ट ने डा.मल्ला को 16 जनवरी तक न्यायिक हिरासत में भेजा

नयी दिल्ली (एजेंसी) दिल्ली की एक अदालत ने 10 नवंबर को लालकिले के पास हुए विस्फोट मामले के आरोपियों में से एक डॉ. बिलाल नसीर मल्ला को 16 जनवरी तक 13 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) ने शनिवार को मल्ला को कड़ी सुरक्षा के बीच पटियाला हाउस अदालत में पेश किया। मल्ला को 26 दिसंबर को आठ दिन के लिए एनआईए की हिरासत में भेजा गया था और एजेंसी ने उसकी हिरासत अवधि समाप्त होने पर उसे अदालत में पेश किया। मीडियाकर्मियों को कार्यवाही कवर करने से रोक दिया गया था। आरोपी को प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अंजू बजाज चांदना के समक्ष पेश किया गया, जिन्होंने मल्ला को 16 जनवरी तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया। एनआईए ने नौ दिसंबर को मल्ला को दिल्ली में गिरफ्तार किया था और उसे साजिश का मुख्य आरोपी बताया था। एनआईए की जांच के अनुसार, मल्ला ने जानबूझकर डॉ. उमर–उन–नबी को रसद संबंधी सहायता प्रदान की थी। नबी आत्मघाती हमलावर था, जो वह विस्फोटक से भरी आई20 कार चला रहा था जिसमें 10 नवंबर को लालकिले के बाहर हुए विस्फोट में 15 लोग मारे गए थे। एजेंसी ने नौ दिसंबर को बताया कि मल्ला पर आतंकवादी हमले से संबंधित सबूतों को नष्ट करने का भी आरोप है। एनआईए ने इस मामले में अब तक नौ लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें तीन डॉक्टर – मुजम्मिल गनई, अदील राथर और शाहीन सईद और एक धार्मिक उपदेशक मौलवी इरफान अहमद वागे शामिल है। अन्य पांच में मल्ला, अमीर राशिद अली, सोयब, जसीर बिलाल वानी उर्फ घ्धानिश और यासिर अहमद डार शामिल हैं।

उन्नाव रेप केसः कुलदीप सेंगर की बेटी ने अमित शाह को लिखी चिट्ठी, कहा- हमें मिले स्थायी सुरक्षा... अनहोनी का जताया डर

लखनऊ (एजेंसी) उन्नाव बलात्कार मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे पूर्व भाजपा विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की बेटी ऐश्वर्या सेंगर ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को एक भावुक पत्र लिखा है। इसमें उन्होंने पीड़िता और उसके परिवार को निरंतर सुरक्षा प्रदान करने की गुहार लगाई है, ताकि किसी अप्रिय घटना पर उनके पिता पर फिर से आरोप न लगे। ऐश्वर्या ने पत्र में चिंता व्यक्त की कि पीड़िता सोशल मीडिया और मीडिया पर बार–बार बयान दे रही हैं कि यदि कुलदीप सेंगर को जमानत या रिहाई मिली तो वह या उनका परिवार आत्महत्या कर लेगा। ऐश्वर्या का कहना है कि ऐसे बयानों से डर का माहौल बन रहा है और अगर पीड़िता पक्ष के साथ कोई हादसा हुआ तो सारा ठीकरा उनके पिता के सिर फोड़ा जाएगा। पत्र में पुरानी घटनाओं का हवाला देते हुए ऐश्वर्या ने याद दिलाया कि 2018 में पीड़िता ने मुख्यमंत्री आवास के सामने आत्मदाह की कोशिश की थी, जिसके बाद मीडिया दबाव में उनके पिता को गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं, 2019 की सड़क दुर्घटना में पीड़िता घायल हुई और उनके रिश्तेदारों की मौत हुई, लेकिन सीबीआई, आईआईटी दिल्ली, सीएफएसएल और सीआरआरआई की जांच में इसे स्पष्ट दुर्घटना माना गया। दिल्ली कोर्ट ने इस मामले में सेंगर को बरी कर दिया और कोई अपील नहीं हुई, फिर भी मीडिया में हत्या के प्रयास का आरोप लगाया जाता रहा। ऐश्वर्या ने मीडिया पर पक्षपातपूर्ण कवरेज का आरोप लगाते हुए कहा कि इससे निष्पक्ष ट्रायल का हक छिन गया और हर राहत वाले फैसले पर विरोध शुरू हो जाता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह पत्र केवल न्याय, मानवीयता और किसी अनहोनी को रोकने के लिए है, न कि सहानुभूति के लिए। गौरतलब है कि दिल्ली हाईकोर्ट ने 23 दिसंबर को सेंगर की सजा निलंबित कर जमानत दी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 29 दिसंबर को उस आदेश पर रोक लगा दी। सेंगर अभी जेल में ही हैं।

प्रो रेसलिंग लीग की धमाकेदार वापसी

6 साल बाद मेगा आक्शन आज, 250 स्टार पहलवान होंगे नीलाम

नयी दिल्ली 03 जनवरी (एजेंसी) प्रो रेसलिंग लीग हाई–प्रोफाइल वापसी के लिए तैयार है। आज नयी दिल्ली में होने वाली 2026 प्लेयर नीलामी में 250 से ज़्यादा पहलवानों की बोली लगेगी। यह नीलामी लीग के पांचवें सीजन की तैयारी में एक अहम कदम है, जो छह साल के ब्रेक के बाद फिर से शुरू हो रहा है। नीलामी पूल में पहलवानों को उनके प्रदर्शन और अंतरराष्ट्रीय पहचान के आधार पर चार कैटेगरी में बांटा गया है – ए (मार्की), ए , बी और सी। इन कैटेगरी के लिए बेस प्राइस ए पहलवानों के लिए 18 लाख, कैटेगरी ए के लिए 12 लाख, कैटेगरी बी के लिए 8 लाख और कैटेगरी सी के लिए 3 लाख तय किया गया है, जिससे फ्रेंचाइजी को एक व्यवस्थित और पारदर्शी बोली लगाने का ढांचा मिलता है। नीलामी पूल में कई बड़े नाम, जिनमें जापानी महिला रेसलिंग की दिग्गज यूई सुसाकी, क्यूबा की पेरिस ओलंपिक सिल्वर मेडलिस्ट युस्नेलिस गुजमैन लोपेज और यूक्रेन की दो बार की ओलंपिक मेडलिस्ट इरीना कोलियाडेन्को के साथ–साथ स्थानीय सितारे अमन सहरावत, जो पेरिस ओलंपिक के कांस्य पदक विजेता हैं और भारत की सबसे कम उम्र की ओलंपिक महिला पहलवान और दो बार की विश्व चौंपियनशिप मेडलिस्ट अंतिम पंघाल, ए कैटेगरी में शामिल हैं। कैटेगरी ए में दीपक पूनिया, जो विश्व चौंपियनशिप के रजत पदक विजेता और पूर्व राष्ट्रमंडल खेलों के चौंपियन हैं और हाल ही में अंडर–23 विश्व चौंपियन बने भारत के सुजीत कल्कल के साथ–साथ आर्मेनिया के चार बार के विश्व चौंपियनशिप मेडलिस्ट आर्सेन हारुत्युन्यान, मंगोलिया के पूर्व एशियाई खेलों के चौंपियन और दो बार के विश्व चौंपियनशिप मेडलिस्ट तुलगा और पोलैंड के 2025 विश्व चौंपियनशिप कांस्य पदक विजेता रॉबर्ट बारन जैसे खिलाड़ी शामिल हैं। बी कैटेगरी में नाइजीरियाई महिला कुश्ती की दिग्गज और नौ बार की अफ्रीकी चौंपियन ओडुनायो फोलसाडे, ईरानी हेवीवेट हादी वफाईपुर, आर्मेनियाई विश्व चौंपियनशिप मेडलिस्ट अरमान एंड्रियास्यान, मैक्सिको के मौजूदा पैन–अमेरिकन चौंपियन रोमन गुइलेर्मो ब्रावो यंग और भारतीय महिला कुश्ती स्टार अंशु मलिक जैसे जाने–माने इंटरनेशनल पहलवान शामिल हैं। सी कैटेगरी में, ज्यादातर उभरते हुए भारतीय टैलेंट जैसे अंडर–23 एशियाई चौंपियन जयदीप, चंदरमोहन, मनीषा और प्रिया को कनाडा की मौजूदा पैन–अमेरिकन चौंपियन कार्ला जैसे इंटरनेशनल खिलाड़ियों के साथ जगह मिली है। यह लीग इस सीजन के लिए कुल 12 करोड़ रुपये के बजट के साथ चलेगी, जिसमें छह फ्रेंचाइजी में से हर एक को अपनी टीम बनाने के लिए 2 करोड़ रुपये दिए जाएंगे।टीमें नौ वेट कैटेगरी में मुकाबला करेंगी, पांच पुरुषों की और चार महिलाओं की। हर फ्रेंचाइजी को कम से कम नौ और ज़्यादा से ज़्यादा बारह पहलवानों की एक टीम बनानी होगी, जिसमें पांच पुरुष और चार महिलाएं शामिल होंगी। कुल टीम में से, चार पहलवान विदेशी एथलीट होने चाहिए, दो पुरुष और दो महिलाएं, जिससे टीमों में एक मजबूत इंटरनेशनल मौजूदगी सुनिश्चित हो सके। इसके अलावा, हर टीम में कम से कम एक पहलवान कैटेगरी सी से होना चाहिए, यह प्रावधान उभरते हुए टैलेंट को बढ़ावा देने और मुकाबले के अवसरों को बढ़ाने के लिए बनाया गया है। प्रो रेसलिंग लीग 2026, 15 जनवरी से 1 फरवरी 2026 तक आयोजित की जाएगी, और इसमें टॉप भारतीय और इंटरनेशनल कुश्ती टैलेंट के साथ हाई–इंटेंसिटी मुकाबले होने की उम्मीद है।

अबार जितबे बांग्ला यात्रा ने बदला बंगाल का सियासी समीकरण! ममता की एंट्री से मचेगा तहलका

कोलकाता (एजेंसी)। पश्चिम बंगाल में 2026 विधानसभा चुनावो को लेकर सियासी पारा हाई हो गया है। टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव और डायमंड हार्बर से सांसद अभिषेक बनर्जी ने दक्षिण 24 परगना के बरुईपुर से अपने व्यापक राज्यव्यापी अभियान 'अबार जितबे बांग्ला' (बंगाल फिर जीतेगा) का आगाज किया। 1 महीने तक चलने वाली इस यात्रा का पूरा फोकस विधानसभा चुनाव पर होगा। इसके पहले दिन अभिषेक बनर्जी ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा, तो साथ ही बड़ी चेतावनी भी दे दी है।अभियान की शुरुआत करते हुए अभिषेक बनर्जी ने कहा–ष्अभी तो मैं सबसे आगे चल रहा हूं... सोचिए, जब खुद ममता दी इस लड़ाई को लीड करेंगी, तो क्या तहलका मचेगा!इस दौरान अभिषेक बनर्जी ने सरकार पर आर्थिक भेदभाव का आरोप लगाया उन्होंने कहा कि पिछले 5 वर्षों से बीजेपी सरकार ने (मनरेगा) का भुगतान रोक रखा है..बंगाल में बीजेपी की हार का बदला राज्य की जनता से लिया जा रहा है और विकास के पैसे रोके जा रहे हैं। बनर्जी ने अपना हमला जारी रखते हुए कहा कि बंगाल में बीजेपी हारी तो उसने बंगाल के सभी पैसे बद कर दिए।इस दौरान उन्होंने साफ किया कि टीएमसी का संकल्प है कि वो बीजेपी की इस शविभाजनकारी राजनीतिश को ध्वस्त कर बंगाल के हक की लड़ाई लड़ेगी..टीएमसी की इस यात्रा ने पहले दिन ही राज्य का सियासी पारा चरम पर पहुंचा दिया है..वहीं जिस तरह अभिषेक ने ममता बनर्जी के इस यात्रा में शामिल होने की बात कही..उससे माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में बंगाल की सियासत और भी गरमाने वाली है।

दिल्ली-एनसीआर की हवा हुई साफ, लेकिन येलो अलर्ट जारी... दूसरे शहरों में कोहरे के कारण 72 उड़ानें रद्द

नयी दिल्ली (एजेंसी) राजधानी में शनिवार सुबह हवा की स्थिति में मामूली सुधार दर्ज किया गया। मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने सुबह के समय घने कोहरे के कारण श्येलो अलर्टश जारी किया। इस कोहरे के कारण दृश्यता प्रभावित रही। सुबह करीब आठ बजे राष्ट्रीय राजधानी में वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 235 दर्ज किया गया। दिल्ली के आनंद विहार में एक्यूआई 248, रोहिणी में 270, आईटीओ में 219, इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा में 148 दर्ज किया गया। दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर शनिवार को खराब मौसम के कारण 72 उड़ानें रद्द रहीं और 300 से अधिक की उड़ानों की आवाजाही में देरी हुई। दिल्ली में आज सुबह कोहरा नहीं था, लेकिन देश के दूसरे हिस्सों में कोहरे के कारण वहां से आने वाली और वहां जाने वाली उड़ानें रद्द रहीं। हवाई अड्डे के अधिकारियों ने बताया कि विभिन्न विमान सेवा कंपनियों ने आज दिल्ली आने वाली 34 और यहां से जाने वाली 38 उड़ानें रद्द कीं। इसके अलावा 300 से अधिक उड़ानों में देरी की भी सूचना है। उल्लेखनीय है कि आज दिल्ली में रनवे पर दृश्यता ठीक रही, लेकिन दूसरे शहरों में कोहरा रहा। विमान सेवा कंपनियों ने धर्मशाला, भुवनेश्वर, इंदौर, दरभंगा और हैदराबाद में कोहरा होने की सूचना देते हुए यात्रियों को अपनी उड़ान की ताजा स्थिति जानने के लिए वेबसाइट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर संपर्क करने की सलाह दी है।

अयोध्या की तीन मुख्य घटनाएं

अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम के नव्य–भव्य मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की दूसरी वर्ष गांठ 2025 के अंतिम दिन अर्थात 31 दिसम्बर को सम्पन्न हुई। यह प्रतिष्ठा द्वादशी इसलिए भी ज्यादा महत्वपूर्ण रही क्योंकि साल में दो बार इसका आयोजन हुआ। पौष शुक्ल पक्ष द्वादशी को प्राण प्रतिष्ठा समारोह हुआ था। इसी के अनुसार वर्ष 2025 में पहले जनवरी में प्राण प्रतिष्ठा की वर्षगांठ मनायी गयी थी और 31 दिसंबर को पुनः इसी तिथि पर आयोजन हुआ। इस समारोह में केन्द्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विशेष रूप से उपस्थित थे। योगी आदित्यनाथ ने इस अवसर पर तीन मुख्य घटनाओं का उल्लेख किया। ये तीन मुख्य घटनाएं पिछले 11 वर्षों की हैं जब से केन्द्र कमें भाजपा की सरकार आयी। योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या के संघर्ष को भी याद किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भी संदेश भेजा था। इस संदेश में असंख्य रामभक्तों के संघर्ष को याद किया। मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम ने जिस तरह निसिचर हीन करौं महि... की प्रतिज्ञा की थी उसी तरह योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश को अपराधी विहीन करने का संकल्प लिया था। यूपी की पुलिस ने 2017 से 2025 तक का आंकड़ा जारी किया है जो बताता है कि इस अवधि में कितने अपराधी मारे गये। योगी आदित्यनाथ ने 20 मार्च 2017 को उत्तर प्रदेश की कमान संभाली थी।

अयोध्या में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सनातन धर्म से ऊपर कोई नहीं है। कुछ लोगों ने अयोध्या से षड्यंत्र किया। अयोध्या में राम मंदिर परिसर में प्राण प्रतिष्ठा द्वादशी के अवसर पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने ये बातें कहीं। सीएम योगी ने कहा, पिछले 11 वर्षों में पीएम मोदी के यशस्वी नेतृत्व में उन तीन अहम घटनाओं को विस्मृत नहीं किया जा सकता। याद करिए 5 अगस्त 2020 जब देश का कोई पीएम स्वयं अयोध्या धाम पधारा और 500 वर्षों के कलंक को समाप्त करते हुए अपने करकमलों से राम जन्मभूमि के कार्यक्रम को संपन्न किया था।

सीएम योगी ने आगे कहा, दूसरी तारीख 22 जनवरी 2024 को पीएम मोदी स्वयं अयोध्या पधारे और श्री रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को अपने कर कमलों से संपन्न किया। तीसरा जब अभी 25 नवंबर को विवाह पंचमी के शुभ अवसर पर प्रधानमंत्री स्वयं आए और राम मंदिर के मुख्य शिखर पर उन्होंने सनातन धर्म की ध्वजा को प्रतिष्ठित करके सनातन से ऊपर कोई नहीं का संदेश दिया। सनातन की पताका यूं ही लहराती रहेगी, यह संदेश पूरी दुनिया को दिया। सीएम योगी ने कहा, अयोध्या ने जो संघर्ष देखा था.. पिछली सरकार ने अयोध्या को लहूलुहान करने का काम किया था। उन्होंने शासन में आतंकी हमले कर अयोध्या को लहूलुहान करने का प्रयास हुआ था। लेकिन प्रभु की कृपा और बजरंग बली जहां की रक्षा स्वयं कर रहे हों वहां तो भूत पिशाच निकट नहीं आवे.. महावीर जब नाम सुनावे.. यहां तो हनुमान जी स्वयं विराजमान हैं, फिर कोई आतंकी यहां कैसे प्रवेश कर जाता।

अयोध्या में रामलला मंदिर की प्राण–प्रतिष्ठा की द्वितीय वर्षगांठ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी देशवासियों के लिए संदेश दिया है, जिसमें 5 सदियों के संघर्ष की गूंज है। उनके पोस्ट में उस भारत की तस्वीर भी झलकती है, जहां संस्कार, आस्था और आत्मनिर्भरता एक–दूसरे से जुड़ते नजर आते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर किए पोस्ट में पीएम मोदी ने ये भी कामना की कि हर भारतवासी के दिल में समर्पण और करुणा की भावना बढ़े। पीएम मोदी ने पोस्ट किया, अयोध्या जी की पावन धरा पर आज रामलला की प्राण–प्रतिष्ठा की द्वितीय वर्षगांठ मनाई जा रही है। ये वर्षगांठ हमारी आस्था और संस्कारों का एक दिव्य उत्सव है। इस पावन–पुनीत अवसर पर देश–विदेश के सभी रामभक्तों की ओर से प्रभु श्री राम के चरणों में मेरा कोटि–कोटि नमन और वंदन! समस्त देशवासियों को मेरी अनंत शुभकामनाएं। अपने अगले पोस्ट में प्रधानमंत्री ने लिखा, भगवान श्री राम की असीम कृपा और आशीर्वाद से असंख्य रामभक्तों का पांच सदियों का संकल्प साकार हुआ है। आज रामलला अपने भव्य धाम में पुनः विराजित हैं और इस वर्ष अयोध्या की धर्म ध्वजा, रामलला की प्रतिष्ठा द्वादशी की साक्षी बन रही है। ये मेरा सौभाग्य है कि पिछले महीने मुझे इस ध्वजा की पुण्य स्थापना का सुअवसर मिला। प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी लिखा, मेरी कामना है कि मर्यादा पुरुषोत्तम की प्रेरणा हर देशवासी के हृदय में सेवा, समर्पण और करुणा की भावना को और प्रगाढ़ करे, जो समृद्ध और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण का सशक्त आधार भी बने। जय सियाराम!

गौरतलब है कि अयोध्या के राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा 2 साल पहले 22 जनवरी 2024 को संपन्न हुई थी। इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में पीएम मोदी मुख्य यजमान के तौर पर शामिल हुए थे और उसी दिन रामलला अपने भव्य मंदिर के गर्भगृह में विराजित हुए थे।मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का धर्म और कर्म साथ–साथ चलता है। मर्यादा की स्थापना के लिए कानून–व्यवस्था का कठोर होना भी जरूरी है। उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्ण ने इस बात की जानकारी साझा की है कि साल 2025 में उत्तर प्रदेश में कितने अपराधियों का एनकाउंटर किया गया है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी बताया है कि साल 2017 से अब तक राज्य में कितने एनकाउंटर हुए। इन एनकाउंटरों में कितने अपराधी मारे गए और कितने घायल हुए हैं। डीजीपी राजीव कृष्ण ने बताया है कि साल 2025 में यूपी में पुलिस के साथ मुठभेड़ के दौरान 48 बदमाश मारे गए हैं। बता दें कि ये आंकड़ा बीते 8 साल में सबसे ज्यादा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए डीजीपी ने बताया कि साल 2025 में भी पुलिस कानून व्यवस्था को दुरुस्त रखने के लिए पूरी तरह से एक्टिव रही। 2025 में राज्य में कुल 2739 मुठभेड़ हुए हैं। इनमें 48 अपराधी मारे गए हैं। इसके साथ ही 3153 अपराधी जख्मी भी हुए हैं। दी गई जानकारी के मुताबिक, साल 2017 से अब तक उत्तर प्रदेश में पुलिस के साथ कुल 16,284 एनकाउंटर हुए हैं। पुलिस की ओर से इन मुठभेड़ों में 266 अपराधियों को ढ़ेर किया गया है। इसके साथ ही 10,990 बदमाश घायल भी हुए हैं। राजीव कृष्ण ने बताया है कि यूपी पुलिस राज्य में कानून–व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए लगातार प्रयासरत है। उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा ने इस दौरान माफिया अपराधियो की 4137 करोड़ रुपये की संपत्ति या तो जब्त की गई या बुल्डोजर से ध्वस्त की गई है। इसके अलावा धार्मिक स्थलों से 1,17,145 लाउडस्पीकर हटवाए गए हैं। वहीं, 1,85,468 लाउडस्पीकरों की आवाज कम की गई है।

शासन माफिया व अपराधियों पर जीरो टालरेंस के तहत कार्रवाई कर रहा। प्रदेश के सूचीबद्ध माफिया की बात करें तो इनमें पांच माफिया फरार हैं, जिनकी पुलिस लंबे समय से तलाश कर रही है। जबकि बृजेश सिंह समेत बीस माफिया जमानत पर बाहर हैं। पुलिस उनकी गतिविधियों पर नजर रखने के साथ ही उनके मुकदमों में और प्रभावी पैरवी की रणनीति के तहत कदम बढ़ा रही है। चिन्हित 66 माफिया की सूची में शामिल रहे अतीक अहमद की पुलिस अभिरक्षा में हत्या हो चुकी है और पुलिस अभिरक्षा से भाग निकले आदित्य राणा उर्फ रवि मुठभेड़ में मारा गया था। भू–माफियाओं द्वारा सरकारी एवं निजी सम्पत्तियों पर अवैध कब्जा करने की शिकायतें शासन एवं प्रशासन स्तर पर प्राप्त होती रहती हैं। ऐसे अतिक्रमणकर्ताओं, भूमाफियाओं को चिन्हित कर उनके विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही किया जाना आवश्यक है, ताकि जनमानस में सुरक्षा की भावना उत्पन्न हो। (हिफी)

सम्पादकीय

उम्मीद-ए-सहर की बात सुनो!

नई सुबह और नई उम्मीदों के साथ नए साल का स्वागत है। बीता हुआ साल अच्छा नहीं था। अप्रैल में पहलगाम में बड़ा आतंकवादी हमला हुआ था, जिसमें देश के अलग अलग हिस्सों के 25 बेकसूर सैलानियों और एक स्थानीय कश्मीर व्यक्ति की हत्या कर दी गई थी। उसके बाद भारत ने जवाबी कार्रवाई में श्ऑपरेशन सिंदूरश्य के जरिए छह और सात मई की दरम्यानी रात को आतंकवादी ठिकानों को नष्ट किया लेकिन दुर्भाग्य से यह ऑपरेशन पाकिस्तान के साथ सीमित युद्ध में बदल गया।

पहले के बालाकोट या उरी स्ट्राइक से उलट पाकिस्तान ने जवाबी हमला कर दिया। इसका अंत 10 नवंबर को बिल्कुल अप्रत्याशित तरीके से हुआ। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सीजफायर का ऐलान किया। उसके बाद से वे करीब एक सौ बार कह चुके हैं कि उन्होंने व्यापार बंद करने और टैरिफ बढ़ाने का दबाव डाल कर भारत और पाकिस्तान को सीजफायर के लिए तैयार कराया। इसके बाद साल के अंत में राजधानी दिल्ली में लाल किले के सामने कार बम धमाका हुआ, जिसमें एक दर्जन से ज्यादा लोग मारे गए। इन दो घटनाओं ने सरकार के बनाए सुरक्षा नैरेटिव को पूरी तरह से बदल दिया।

जुलाई का महीना एक अलग स्ट्राइक लेकर आया, जब राष्ट्रपति ट्रंप ने अमेरिका जाने वाले भारत के उत्पादों पर पर 25 फीसदी का टैरिफ लगाया और रूस से तेल खरीदने की सजा देते हुए 25 फीसदी का अतिरिक्त टैरिफ लगाया। इसके बाद से भारतीय मुद्रा यानी रुपए में गिरावट का ऐसा सिलसिला चला है कि एक डॉलर 90 रुपए से ज्यादा का हो गया है। भारत के पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में पूरी तरह से भारत विरोधी माहौल बन गया है, जिसका फायदा पाकिस्तान और चीन दोनों उठा रही हैं। शेख हसीना के तख्तापलट और उनके भारत आने के बाद से हिंदुओं पर हो रहे हमलों में पिछले साल अचानक तेजी आई।

हिंदुओं पर हमले की दर्जनों घटनाएं हुई हैं और दिसंबर 2025 के आखिरी 15 दिन में तीन हत्याएं हुईं। वहां हालात 1971 जैसे बन रहे हैं और उसी तरह शरणार्थियों के भारत की सीमा पर जमा होने की आशंका बन गई है। नेपाल में भी सत्ता परिवर्तन हुआ और केपी शर्मा ओली का तख्तापलट करा कर जेन जी ने सुशीला कार्की को सत्ता सौंपी। एक तरह से पूरा साल भारत के लिए सामरिक नीति, कूटनीति और अर्थनीति तीनों में नैरेटिव गंवाने का रहा। दुनिया निश्चित रूप से दुविधा में रही कि श्ऑपरेशन सिंदूरश्य में सचमुच क्या हुआ था? उधर पाकिस्तान ने दुनिया की तीनों महाशक्तियों अमेरिका, रूस और चीन का सद्भाव हासिल किया। उसके सेना प्रमुख का व्हाइट हाउस में स्वागत हुआ।

अगर घरेलू राजनीति की बात करें तो सरकार का विपक्ष के साथ टकराव बढ़ता गया है। 2024 में लोकसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन के बाद भाजपा की जीत का जो सिलसिला हरियाणा, महाराष्ट्र में बना वह 2025 में दिल्ली और बिहार में जारी रहा। लेकिन लगातार जीत के बावजूद भाजपा का शीर्ष नेतृत्व लोकसभा में बहुमत गंवाने के बाद से सहज नहीं हो पाया है। मुख्य विपक्षी पार्टी ने श्वोट चोरीश्य को ऐसा मुद्दा बनाया है, जिससे देश की पूरी चुनाव प्रक्रिया संदेह के घेरे में आई है। दुर्भाग्य की बात है कि चुनाव आयोग लोगों का संशय दूर करने की बजाय विपक्ष के विरोधी की तरह बरताव कर रहा है। विपक्ष की दूसरी पार्टियां श्वोट चोरीश्य के मामले में भले कांग्रेस के साथ पूरी तरह से सहमत नहीं हैं लेकिन संसद में चुनाव सुधार पर चर्चा के दौरान सबने चुनाव आयोग के पक्षपात का मुद्दा बनाया। चुनाव प्रक्रिया पर बन रहा अविश्वास अंततरू लोकतंत्र को कमजोर करेगा। मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर एक सही कदम है लेकिन इसे जिस तरह से जल्दबाजी में लागू किया गया उससे संदेह पैदा हुआ है। 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में हुई एसआईआर की प्रक्रिया में कई तरह की कमियां सामने आई हैं। भारत में राजनीति का विभाजन जितना गहरा हुआ है उसी अनुपात में समाज का विभाजन भी बढ़ा है। यह सामाजिक विभाजन लंबे समय में भारत की एकता और अखंडता को प्रभावित करने वाला होगा।

सो, नए साल में गालिब की तरह यह तो नहीं कह सकते हैं कि, श्एक बिरहमन ने कहा है कि ये साल अच्छा हैश्य, लेकिन फैज की तरह श्सहर की बात उम्मीद–ए–सहर की बातश्य यानी कर सकते हैं। उम्मीद कर सकते हैं कि सब कुछ ठीक होगा। भारत ने ब्रिटेन से लेकर न्यूजीलैंड कर सात देशों के साथ मुक्त व्यापार संधि की है और उम्मीद है कि नए साल में जनवरी या फरवरी में अमेरिका के साथ व्यापार संधि हो जाएगी। अमेरिका के साथ व्यापार संधि से बहुत कुछ बदलेगा। भारत का अलगाव समाप्त होगा। टैरिफ कम होगा, जिससे निर्यात बढ़ेगा और आर्थिकी पर दबाव कम होगा। यूरोपीय संघ के साथ भी भारत की व्यापार वार्ता अंतिम चरण में है। इससे भारत की आर्थिकी में एक ठहराव आने की उम्मीद है। अमेरिका के साथ व्यापार संधि होने के बाद कूटनीतिक मोर्चे पर भी भारत को निश्चित रूप से फायदा होगा। नेपाल में भी नए साल के शुरू में चुनाव होने वाले हैं। वहां भी राजनीतिक स्थिरता आती है तो भारत के लिए बेहतर होगा।

नए साल में फरवरी में बांग्लादेश में चुनाव होना वाले हैं। हालांकि शेख हसीना की आवामी लीग के चुनाव लड़ने पर पाबंदी है लेकिन बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी चुनाव लड़ रही है। बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री रहीं बेगम खालिदा जिया का निधन हो गया है लेकिन उससे ठीक पहले उनके बेटे तारिक रहमान अपने वतन लौट आए और चुनाव में अपनी पार्टी बीएनपी का नेतृत्व कर रहे हैं। जनरल इरशाद की जातीय पार्टी भी मुकाबले में है। जमात ए इस्लामी भी चुनाव लड़ रही है। सो, चुनाव लड़ रही लगभग सभी पार्टियों का रुख भारत विरोधी रहा है। फिर भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत चुनी गई सरकार के साथ संवाद बहाल बेहतर होगा और उम्मीद कर सकते हैं कि हिंदुओं पर हमले रुकेंगे।अंतरराष्ट्रीय और आर्थिक मोर्चे पर स्थिरता के बाद भी ऐसा लग रहा है कि नए साल में लेकिन घरेलू राजनीति का मैदान टकराव वाला बना रहेगा। अप्रैल और मई में पांच राज्यों पश्चिम बंगाल, असम, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में विधानसभा के चुनाव हैं। पश्चिम बंगाल और असम का चुनाव बहुत ज्यादा कटुता बढ़ाने वाला होगा। भारत में चुनाव पिछले कुछ समय से जंग की तरह लड़े जा रहे हैं। इसमें इतनी कटुता पैदा होती है कि चुनाव के बाद भी वह समाप्त नहीं होती है। पहले पार्टियां और देश की जनता भी चुनाव के समय राजनीतिक टकराव के मोड में आती थी और चुनाव के बाद सब पहले जैसा सामान्य हो जाता था। लेकिन अब सालों भर राजनीति और समाज की खदबदाहट बनी रहती है।

नासिक में कुश्ती, मुंबई में दोस्ती

महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन अर्थात् भारतीय जनता पार्टी (भाजपा), शिवसेना (शिंदे) और एनसीपी (अजित पवार) महानगर परिषद के चुनावों में कहीं दोस्ती के साथ मिलकर लड़ेंगी तो कहीं कुश्ती भी होगी। महानगर परिषद चुनाव 15 जनवरी 2026 को होंगे। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माने जा रहे मुंबई महानगर निगम (बीएमसी) भाजपा व शिवसेना मिलकर लड़ेंगे तो नासिक में एकनाथ शिंदे और अजित पवार देवेन्द्र फडणवीस को ही टक्कर देंगे। बीएमसी चुनाव में अजित पवार की पार्टी अलग से प्रत्याशी खड़े कर रही है। उधर, विपक्ष की तरफ से कांग्रेस ने 29 दिसम्बर को ही 87 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी थी। वर्ष 2017 में हुए बीएमसी चुनाव में सबसे ज्यादा सीटें अविभाजित शिवसेना को मिली थीं।

बीएमसी चुनाव के लिए बीजेपी और शिवसेना में गठबंधन हो गया और सीट शेयरिंग भी फाइनल हो गई। बीजेपी 137 सीटों पर तो वहीं शिवसेना 90 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। मुंबई महानगर पालिका में 227 वार्ड हैं। पिछले कई दिनों से दोनों दलों के बीच सीटों को लेकर खींचतान चल रही थी। आखिरकार सीटों का फॉर्मूला तय हो गया।

महायुति में शामिल एनसीपी बीजेपी और शिवसेना के साथ मुंबई का चुनाव नहीं लड़ रही है। अजित पवार की एनसीपी ने रविवार को पहली सूची जारी करते हुए 37 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा। वहीं 29 दिसम्बर को 27 नामों की घोषणा की। इस तरह से एनसीपी ने मुंबई के लिए 30 दिसम्बर तक 64 कैंडिडेट का ऐलान कर दिया था। इससे पहले बीजेपी ने सोमवार (29 दिसंबर) को बीएमसी चुनाव के लिए उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की। इस लिस्ट में 2017 में बीएमसी चुनाव जीतने वाले कुछ पार्षदों के नाम भी शामिल हैं। उम्मीदवारों में सबसे प्रमुख नाम बीजेपी के राज्य मीडिया प्रमुख नवनाथ बान का है, जो उम्मीदवारों में सबसे युवा हैं। बान शिवाजीनगार क्षेत्र के वार्ड नंबर 135 से चुनाव लड़ेंगे। मुंबई समेत महाराष्ट्र के 29 नगर निगमों का चुनाव 15 जनवरी को होगा। मतगणना अगले दिन होगी।बीएमसी में कुल 227 वार्ड हैं और मतदाताओं की संख्या 1 करोड़ 3 लाख 44 हजार 315 है। इनमें 55 लाख 16 हजार 707 पुरुष, 48 लाख 26 हजार 509 महिलाएं और 1099 'अन्य' श्रेणी के मतदाता शामिल हैं। मतदाताओं में पुरुषों की हिस्सेदारी 53 फीसदी और महिलाओं की 47 फीसदी है। साल 2017 के बीएमसी चुनावों में अविभाजित शिवसेना 84 सीट जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनी थी, जबकि बीजेपी को 82 सीटें मिली थीं। शिवसेना के 84 पार्षदों में से 46 बाद में शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना में शामिल हो गए, वहीं अन्य दलों के 16 पार्षद भी शिंदे गुट में आए। बीजेपी में अन्य दलों के छह पार्षद शामिल हुए हैं। उधर, नासिक नगर निगम (एनएमसी) चुनावों में महायुति के सहयोगी दलों बीजेपी और शिवसेना–एनसीपी तथा महाविकास आघाडी के बीच त्रिकोणीय मुकाबला होता दिखायी दे रहा है। नेताओं ने सोमवार (29 दिसंबर) को यह कहा। बीजेपी ने चुनाव में अकेले उतरने का फैसला किया है, जबकि उसके सहयोगी दल, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) और शिवसेना एक साथ आ गए हैं।दूसरी ओर, सूत्रों के अनुसार, महा विकास आघाडी (एमवीए) ने चुनाव साथ–साथ लड़ने का लगभग फैसला कर लिया है। राज्य के मंत्री और राकांपा नेता नरहरि जिरवाल ने कहा कि एमवीए ने गठबंधन को लेकर कोई संदेश नहीं दिया है।नामांकन दाखिल करने के एक दिन पहले शिवसेना (एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली) और एनसीपी ने नासिक महानगरपालिका (एनएमसी) चुनाव एक साथ लड़ने का फैसला किया है। नरहरि जिरवाल ने पत्रकारों से कहा, "कौन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा, इस पर कोई सवाल ही नहीं है। हम चुनाव जीतने की क्षमता के फॉर्मूले के आधार पर लड़ रहे हैं। उसी के अनुसार सीटों का बंटवारा किया जाएगा।'' आरोपशिवसेना के पूर्व सांसद हेमंत गोडसे ने भी जिरवाल की बात दोहराते हुए भाजपा पर सकारात्मक प्रतिक्रिया न देने का आरोप लगाया। इसके अलावा, शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे), एनसीपी (शरदचंद्र पवार) और कांग्रेस, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (एमएनएस) के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगी।उधर, अजित पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी ने 15 जनवरी को होने वाले बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) चुनाव के लिए रविवार (28 दिसंबर) को 37 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की। बीएमसी में कुल 227 वार्ड हैं। पार्टी की विधायक सना मलिक ने मीडिया से बातचीत में कहा कि दूसरी सूची जल्द ही जारी की जाएगी। हालांकि, बीजेपी के नेतृत्व वाले महायुति गठबंधन का हिस्सा होने के बावजूद एनसीपी बीएमसी चुनाव अलग लड़ रही है।

बीएमसी चुनाव के लिए कांग्रेस ने भी 87 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। इसमें माहिम विधानसभा सीट के तहत आने वाली वार्ड नंबर 192 भी शामिल है। सूत्रों की मानें तो इस सीट से राज ठाकरे ने अपना उम्मीदवार उतारने का फैसला किया है। कांग्रेस ने वार्ड नंबर 192 से दीपक बाघमारे को टिकट दिया है। इस सीट से राज ठाकरे ने यशवंत किल्लेदार को उतारा है।

192 वार्ड में साल 2017 में उद्धव ठाकरे की जीत हुई थी। माहिम सीट महाराष्ट्र विधानसभा के दौरान चर्चा में रही क्योंकि यहां से राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे ने चुनाव लड़ा था। हालांकि, उन्हें उद्धव ठाकरे की पार्टी के महेश सावंत ने मात दी थी। मुंबई में कांग्रेस ने किसी बड़े दल के साथ किया गठबंधन नहीं किया है।बीएमसी चुनाव के लिए कांग्रेस ने महाविकास अघाड़ी के दल शिवसेना (यूबीटी) और शरद पवार के साथ गठबंधन नहीं किया है। महाविकास अघाड़ी महाराष्ट्र का मुख्य विपक्षी गठबंधन है जिसका हिस्सा कांग्रेस भी है। कांग्रेस ने शुरुआत से ही मुंबई में अकेले लड़ने का अपना रुख बरकरार रखा है। कांग्रेस ने कोलाबा विधानसभा में आने वाले दो वार्ड, मुंबादेवी में दो वार्ड, मालाबार हिल्स में पांच, भायखला में चार, शिवड़ी में एक, वर्सोवा में चार, अंधेरी वेस्ट में पांच, जोगेश्वरी में दो, गोरेगांव में चार, कुर्ला में तीन, धारावी में तीन, चेंबूर में तीन, मानखुर्द शिवाजी नगर में सात और मलाड में सात वार्डों पर उम्मीदवारों की घोषणा की है।

प्रत्याशियों की सूची जारी होने के बाद मुंबई कांग्रेस की अध्यक्ष वर्षा गायकवाड़ ने कहा, हम लोग हर मुंबईकर के अधिकारों के लिए लड़ेंगे। कांग्रेस इस चुनाव में पूरी तैयारी के साथ उतरी है। हम लोग लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई लड़ेंगे। ये चुनाव चुनौतीपूर्ण है लेकिन मुंबईकर हमारे साथ हैं और हमारी जीत होगी। उधर, राजनीतिक पंडित महाराष्ट्र के लोकसभा और विधानसभा चुनाव देखकर नगर निगम चुनावों पर टिप्पणी करने से बच रहे हैं।

पश्चिम में कम्युनिटी लिविंग का बढ़ता चलन

डॉ. नीलम महेंद्र

लेखिका पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय में हिंदी सलाहकार समिति की सदस्य हैं। हाल ही में एक रिसर्च में यह बात सामने आई कि ब्रिटेन में परिवार के सदस्यों (दादा–दादी, माता–पिता, बच्चे) या गैर–पारिवारिक सदस्यों के साथ एक छत के नीचे रहने का चलन बढ़ रहा है। सिर्फ माता–पिता के साथ ही नहीं, बल्कि ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस और अमेरिका जैसे देशों में सैकड़ों कम्युनिटी लिविंग ग्रुप्स बन गए हैं, जहाँ लोग सस्ते में रहते हैं और अकेलेपन से बचते हैं। वहां समाजशास्त्रियों की रिसर्च में यह बात सामने आई है कि कम्युनिटी लिविंग या मल्टी–जेनरेशनल घरों में रहने वाले लोग अकेले या न्यूक्लियर फैमिली (एकल परिवार) में रहने वालों की तुलना में अधिक संतुष्ट और खुश महसूस करते हैं। नतीजन जो लोग अपने घर का खर्च उठा सकते हैं, वे भी अब कम्युनिटी लिविंग चुन रहे हैं, जिससे यह सिर्फ आर्थिक मजबूरी नहीं, बल्कि वहां एक जीवनशैली का विकल्प बनता जा रहा है। इसके विपरीत हम पर्सनल स्पेस और प्राइवेसी की ओर भाग रहे हैं।आज भारत एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहाँ आर्थिक प्रगति, तकनीकी विकास और वैश्विक पहचान के शोर में एक अत्यंत मौन लेकिन गहरी सामाजिक त्रासदी घट रही है और वो है संयुक्त परिवारों का विघटन। विडंबना यह है कि जिस संयुक्त परिवार व्यवस्था को भारत ने पिछड़ेपन का प्रतीक मानकर त्यागना शुरू किया, वही व्यवस्था आज पश्चिमी देशों में नए सामाजिक समाधान के रूप में अपनाई जा रही है। भारत में संयुक्त परिवारों का विघटन केवल जीवन–शैली का बदलाव नहीं है बल्कि यह हमारे मूल सामाजिक दर्शन से विचलन है। दरअसल भारत में संयुक्त परिवार कभी केवल साथ रहने की व्यवस्था मात्र नहीं रहा। अपितु यह एक ऐसा सांस्कृतिक सुरक्षा कवच था जहाँ बच्चे संस्कार सीखते थे, युवा जिम्मेदारी निभाते थे और बुजुर्ग सम्मान पाते थे। यह वह व्यवस्था थी जिसने बिना किसी मनोवैज्ञानिक परामर्श के पीढ़ियों को भावनात्मक रूप से संतुलित रखा। लेकिन आज वही व्यवस्था "स्पेस", "प्राइवेसी" और "इंडिविजुअल फ्रीडम" जैसे शब्दों के नीचे दम तोड़ रही है।और जब परिवार टूटते हैं, तब केवल दीवारें अलग नहीं होतीं,तब संस्कार, संवेदनाएँ और सामाजिक संतुलन भी दरकने लगता है। आंकड़े इस सामाजिक बदलाव की पुष्टि करते हैं। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NFHS–5, 2019द21) के अनुसार भारत में लगभग 58.2: परिवार अब एकल (न्यूक्लियर) संरचना के हैं, जबकि संयुक्त परिवारों की हिस्सेदारी लगातार घट रही है । यह स्पष्ट संकेत है कि संयुक्त परिवार अब अपवाद बनते जा रहे हैं। शहरीकरण और रोजगार की मजबूरियाँ इस टूटन को और तेज कर रही हैं। शोध बताते हैं कि शहरी युवाओं में स्वतंत्रता और निजता को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की प्रवृत्ति बढ़ी है, जिससे संयुक्त परिवारों के साथ रहना "असुविधाजनक" समझा जाने लगा है । पर क्या सुविधा का अर्थ संवेदना का त्याग होना चाहिए, क्या स्वतंत्रता का अर्थ रिश्तों से मुक्ति है? नतीजन आज भारत में परिवार छोटे हो रहे हैं और समस्याएँ बड़ी। पति–पत्नी दोनों कामकाजी हैं, फिर भी मानसिक थकान बढ़ रही है। बच्चे सुविधाओं से घिरे हैं, फिर भी भावनात्मक रूप से असुरक्षित हैं। और बुजुर्ग,जिनके अनुभव किसी भी समाज की सबसे बड़ी पूँजी होते हैं,आज उपेक्षा और अकेलेपन के शिकार हैं। जिस समाज में कभी बुजुर्ग परिवार का केंद्र होते थे, आज वहीं "ओल्ड एज होम" एक आवश्यक व्यवस्था बनती जा रही है। यह विकास नहीं, यह सामाजिक विफलता का संकेत है। इसके उलट, यदि हम पश्चिमी देशों की ओर देखें तो एक बिल्कुल अलग तस्वीर उभरती है। अमेरिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में अब कम्युनिटी लिविंग, मल्टी–जेनरेशन होम्स और फैमिली सपोर्ट सिस्टम को बढ़ावा दिया जा रहा है। वहाँ सरकारें और समाज यह समझ चुके हैं कि अकेलापन सबसे महँगी बीमारी है,जिसका इलाज न दवाओं से होता है, न धन से। जहाँ भारत संयुक्त परिवार से भाग रहा है, वहीं पश्चिम उसकी ओर आकर्षित ही नहीं हो रहा बल्कि उसे अपना भी रहा है। यह विरोधाभास केवल सामाजिक नहीं, बल्कि बौद्धिक भी है। हमने परंपरा को बोझ समझा, उन्होंने अनुभव को संपत्ति माना। हमने बुजुर्गों को "डिपेंडेंसी" कहा, उन्होंने उन्हें मेंटल स्टेबिलिटी का आधार माना। हम भूल गए कि संयुक्त परिवार व्यवस्था की सबसे बड़ी ताकत थी,सामूहिक उत्तरदायित्व। बच्चे केवल माता–पिता के नहीं, पूरे परिवार के होते थे। किसी एक के गिरने पर पूरा परिवार उसे संभाल लेता था। आज इसके स्थान पर हमने संस्थागत विकल्प चुने हैं ,डे–केयर, ट्यूटर, काउंसलर और केयरटेकर। पर सवाल यह है कि क्या भावनाओं की भरपाई सेवाओं से हो सकती है? हमें यह समझ नहीं पाए कि संयुक्त परिवार व्यक्ति की पहचान को कुचलता नहीं था, (जैसा आज कहा जाता है) बल्कि वह उसे विस्तार देता था। वहाँ व्यक्ति अकेला नहीं होता था क्योंकि वहाँ असफलता साझा होती थी और सफलता सामूहिक। आज भारतीय समाज जिस तनाव, अवसाद और पारिवारिक टूटन से जूझ रहा है, उसका बड़ा कारण यही है कि हमने रिश्तों की लागत को सुविधाओं के तराजू में तौलना शुरू कर दिया है। हम भूल गए कि परिवार कोई अनुबंध नहीं होता, जिसे लाभ–हानि देखकर निभाया जाए। अपितु वह एक उत्तरदायित्व होता है जो पीढ़ियों को जोड़ता है। यह भी सत्य है कि संयुक्त परिवारों में चुनौतियाँ थीं,मतभेद थे, टकराव थे, समझौते थे। लेकिन क्या आधुनिक एकल परिवारों में टकराव नहीं हैं? अंतर केवल इतना है कि वहाँ संभालने वाले अधिक थे, और यहाँ झेलने वाला अकेला। आज आवश्यकता इस बात की नहीं है कि हम अतीत में लौट जाएँ, बल्कि यह समझने की है कि परंपरा और आधुनिकता के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए। दरअसल सरकारें योजनाएँ बना सकती हैं,कानून सहारा दे सकते हैं,लेकिन परिवारों को बचाने का काम केवल समाज कर सकता है।

यदि आज भी हमने इस टूटन को केवल "लाइफस्टाइल चेंज" कहकर नजरअंदाज किया, तो कल इसका परिणाम केवल सामाजिक नहीं, राष्ट्रीय होगा। क्योंकि इतिहास गवाह है कि जिस समाज में परिवार कमजोर पड़ते हैं, वहाँ राष्ट्र की नींव भी धीरे–धीरे दरकने लगती है। अब भी समय है कि हम रुकें, सोचें और तय करें कि हमें अकेले मजबूत दिखना है या साथ मिलकर सच में मजबूत बनना है। क्योंकि घर अलग–अलग हो सकते हैं, लेकिन अगर दिल भी अलग हो जाएँ, तो वह समाज नहीं, भीड़ बन जाती है।

रामनगरी को मिलेगा मंडल स्तरीय अत्याधुनिक फॉरेंसिक लैब

-47 करोड़ की बी ग्रेड फोरेंसिक साइंस लैब को मिली रफ्तार
-अब अयोध्या से बाहर नहीं भेजने पड़ेंगे जांच सैंपल, समय व धन दोनों की होगी बचत
-10266 वर्ग मीटर में आकार ले रही बी ग्रेड लैब, ईपीसी मोड पर चल रहा निर्माण कार्य
-अपराध नियंत्रण और मादक पदार्थों के खिलाफ अभियान को मिलेगी तकनीकी मजबूती

अयोध्या। अपराध जांच के क्षेत्र में भी मनगरी अयोध्या नई ऊंचाइयों को छूने जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दूरदर्शी विजन के तहत यहां मंडल स्तरीय अत्याधुनिक बी–ग्रेड फॉरेंसिक साइंस लैब का निर्माण कार्य तेजी से आगे बढ़ रहा है। लगभग 47 करोड़ रुपये की लागत से बाग बिजेसी के निकट में बन रही यह पांच मंजिला इमारत अपराधियों के लिए कड़ी चुनौती साबित होगी। यह लैब 10266 वर्ग मीटर के विशाल क्षेत्र में फैली हुई है और ईपीसी (इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन) मोड पर इसका निर्माण कार्य जोर–शोर से चल रहा है। पहले अयोध्या और आसपास के जिलों के जांच सैंपल्स को लखनऊ, आगरा या अन्य दूरस्थ फॉरेंसिक लैबों में भेजना पड़ता था, जिससे समय और सरकारी धन दोनों की बर्बादी होती थी। अब यह समस्या जड़ से खत्म हो जाएगी। सैंपल जांच में लगने वाला समय काफी कम हो जाएगा, जिससे न्याय मिलने की प्रक्रिया तेज और प्रभावी बनेगी।इस लैब से अपराध नियंत्रण, विशेषकर मादक पदार्थों के तस्करी और नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान को तकनीकी रूप से और मजबूती मिलेगी। डीएनए टेस्टिंग, बैलिस्टिक जांच, केमिकल एनालिसिस, साइबर फॉरेंसिक और अन्य आधुनिक तकनीकों से लैस यह प्रयोगशाला वैज्ञानिक प्रमाणों के आधार पर अपराधियों को पकड़ने में पुलिस को सक्षम बनाएगी। यह परियोजना न केवल अयोध्या बल्कि आसपास के जिलों के लिए भी वरदान साबित होगी। समय की बचत के साथ–साथ जांच की गुणवत्ता में सुधार से निर्दोषों को जल्द राहत और दोषियों को सजा मिलना सुनिश्चित होगा।रामनगरी में बी ग्रेड फॉरेंसिक साइंस लैब का निर्माण कुल 10266.40 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में किया जा रहा है। जबकि, विभाग के पास मौजूद कुल जमीन 15220 वर्ग मी. में बाकी ओपन स्पेस रहेगा। गृह विभाग के टेक्निकल सेल तथा नियोजन विभाग के समन्वय से ईपीसी मोड पर निर्माण कार्यों को पूरा किया जा रहा है।यूपीपीडब्ल्यूडी की ओर से तैयार कराए गए डीपीआर के मुताबिक इसमें दो मंजिला डॉरमेट्री और गेस्ट हॉउस 395.90 वर्ग मीटर में, गैरेज एन्ड एलायड बिल्डिंग 250.20 वर्ग मीटर में, मैसेंजर व गॉर्ड रूम 89 वर्ग मीटर में, वर्कशॉप 42 वर्ग मीटर में, 1000 किलोवाट से ज्यादा क्षमता का विद्युत व पंप रूम 51.50 वर्ग मीटर में निर्मित कराया जा रहा है। साथ ही, 100 किलो लीटर क्षमता की उपरगामी टंकी, सीसी रोड, इंटरलॉकिंग और बाउंड्रीवॉल जैसे निर्माण कार्यों को पूर्ण किया जा रहा है

उद्योग जगत की पहली पसंद बनता उत्तर प्रदेश, निवेश और औद्योगिक विस्तार को लेकर बढ़ा भरोसा

लखनऊ,(संवाददाता) । बेहतर कानून व्यवस्था, स्थिर प्रशासन और पारदर्शी शासन के चलते उत्तर प्रदेश तेजी से देशभर के उद्योग जगत की पहली पसंद बनता जा रहा है। सुरक्षा और अनुशासन के साथ निष्पक्ष गवर्नेंस ने निवेशकों का भरोसा मजबूत किया है, जिसके परिणामस्वरूप बड़े, मध्यम और छोटे सभी स्तर के उद्योग प्रदेश की ओर आकर्षित हो रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात के दौरान भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष राजीव मेमानी, इण्डिया ग्लाइको लिमिटेड के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक उमाशंकर भरतिया और उद्योग प्रतिनिधि सुनील मिश्रा ने निवेश, इंफ्रास्ट्रक्चर और औद्योगिक विस्तार को लेकर विस्तृत विचार–विमर्श किया। प्रतिनिधियों ने कहा कि वर्तमान में प्रदेश का प्रशासनिक सिस्टम पूरी तरह बदला हुआ है, जमीन पर काम करना आसान हुआ है और परियोजनाएं समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रही हैं।उद्योग प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री के एक ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था के विजन में सक्रिय सहयोग की इच्छा जताई और औद्योगिक विकास को और गति देने पर चर्चा की। डिक्रिमिनलाइजेशन विधेयक लागू होने के बाद उद्योगों का भरोसा और बढ़ा है, वहीं निवेश अनुकूल नीतियों और प्रोत्साहनों के चलते ग्लोबल इन्वेस्टमेंट में भी तेजी आई है। सख्त कानून व्यवस्था के साथ एक्सप्रेसवे, औद्योगिक कॉरिडोर, एयरपोर्ट, लॉजिस्टिक्स हब और बिजली–पानी जैसी बुनियादी सुविधाओं के तेज विकास ने राज्य के औद्योगिक इकोसिस्टम को नई मजबूती दी है।मुख्यमंत्री के साथ संवाद में यह भी स्पष्ट हुआ कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस अब केवल नीति नहीं, बल्कि प्रभावी रूप से जमीन पर लागू हो रहा है। सिंगल विंडो सिस्टम 'निवेश मित्र' के माध्यम से 43 विभागों की 525 से अधिक सेवाएं डिजिटल रूप से उपलब्ध हैं, जिससे उद्योग स्थापना की प्रक्रिया सरल और पारदर्शी बनी है। प्रो–इंडस्ट्री नीतियों और त्वरित निर्णय क्षमता के कारण उत्तर प्रदेश एक विश्वसनीय निवेश राज्य के रूप में उभर रहा है। उद्योग जगत का मानना है कि आने वाले समय में प्रदेश में नए निवेश और औद्योगिक विस्तार की योजनाएं तेज होंगी और औद्योगिक इकाइयों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि देखने को मिलेगी।

उत्तर प्रदेश में महिला और बाल संरक्षण में नई पहलः

बाल गृहों व महिला शरणालयों की 24/7 सीसीटीवी निगरानी से सुरक्षा और पारदर्शिता सुनिश्चित

लखनऊ(संवाददाता)। उत्तर प्रदेश सरकार महिला एवं बाल सुरक्षा, संरक्षण और संस्थागत व्यवस्थाओं में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए लगातार ठोस कदम उठा रही है। इस दिशा में महिला कल्याण विभाग ने एक महत्वपूर्ण पहल के तहत राज्य के बाल गृहों और महिला शरणालयों में 24×7 सीसीटीवी निगरानी की व्यवस्था स्थापित की है।निदेशक महिला कल्याण, संदीप कौर ने बताया कि यह पहल अप्रैल 2025 से महिला कल्याण निगम, बंगला बाजार स्थित भवन में स्थित स्टेट डाटा मैनेजमेंट सेंटर (ैक्डब्) के माध्यम से संचालित की जा रही है। इस व्यवस्था के अंतर्गत प्रदेश के 60 बाल गृहों और 10 महिला शरणालयों में कुल 70 संस्थाओं में सीसीटीवी कैमरे स्थापित किए गए हैं।इस व्यवस्था के तहत 17 मंडलों के 15 मंडलीय कार्यालयों और 31 जनपदों के 28 जनपदीय कार्यालयों में भी डिस्प्ले लगाए गए हैं, ताकि अधिकारियों को स्थानीय स्तर पर संस्थाओं की स्थिति का प्रत्यक्ष अवलोकन हो सके। शेष 5 कार्यालय (चित्रकूट, अयोध्या, सहारनपुर) में कार्य प्रगति पर है और इसे एक सप्ताह के भीतर पूरा किया जाएगा।मुख्यालय स्तर पर स्थापित अत्याधुनिक SDMC में 6 प्रशिक्षित कर्मचारी 3 शिफ्टों में 24×7 संचालन सुनिश्चित कर रहे हैं। इसके माध्यम से संस्थाओं में साफ–सफाई, स्टाफ की उपस्थिति, बच्चों के प्रति व्यवहार, किचन की स्वच्छता, सुरक्षा गार्डों की सतर्कता और निवासरत बच्चों की देख–रेख जैसे महत्वपूर्ण बिंदुओं पर निरंतर निगरानी रखी जा रही है।श्रीमती संदीप कौर ने कहा कि यह पहल बाल संरक्षण और महिला सुरक्षा को मजबूत करने के साथ–साथ संस्थागत कार्यप्रणाली में पारदर्शिता और जवाबदेही को भी नई मजबूती देती है। ैक्डब् द्वारा किसी भी प्रकार की लापरवाही या मानकों के उल्लंघन की स्थिति में तुरंत संबंधित अधिकारियों को सूचना दी जाती है, जिससे समयबद्ध सुधारात्मक कार्रवाई संभव हो सके।यह पहल प्रदेश में महिला और बाल कल्याण के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण और अनुकरणीय कदम के रूप में देखी जा रही है, जो सुरक्षा, निगरानी और प्रशासनिक जवाबदेही को सुनिश्चित करती है।

लखनऊविश्वविद्यालय को मिला नया कुलपति, प्रो. जय प्रकाश सैनी नियुक्त

लखनऊ(संवाददाता)। लखनऊ विश्वविद्यालय को नया कुलपति नियुक्त किया गया है। कुलाधिपति आनंदीबेन पटेल ने उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा–12 की उपधारा–1 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रो. जय प्रकाश सैनी को लखनऊ विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त करने का आदेश जारी किया है। यह नियुक्ति कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से आगामी तीन वर्ष की अवधि के लिए प्रभावी होगी।राज भवन, लखनऊ से 03 जनवरी, 2026 को जारी आदेश के अनुसार प्रो. जय प्रकाश सैनी वर्तमान में मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, गोरखपुर के कुलपति के पद पर कार्यरत हैं। उन्हें अब लखनऊ विश्वविद्यालय की अकादमिक, प्रशासनिक एवं शैक्षणिक जिम्मेदारियाँ सौंपी गई हैं।कुलाधिपति द्वारा जारी आदेश की प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु संबंधित अधिकारियों को प्रेषित कर दी गई है, जिसमें उच्च शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन, मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय गोरखपुर तथा लखनऊ विश्वविद्यालय के कुलसचिव शामिल हैं।उल्लेखनीय है कि लखनऊ विश्वविद्यालय नैक द्वारा ए ग्रेड से प्रत्यायित है ।

ग्राम चौपालों के जरिए गांव में ही हो रहा समस्याओं का समाधान, हजारों ग्रामीणों को मिल रही राहत

लखनऊ(संवाददाता)। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के नेतृत्व और निर्देशन में ग्रामीणों की समस्याओं के त्वरित समाधान के उद्देश्य से प्रदेश के प्रत्येक विकास खंड की दो ग्राम पंचायतों में प्रत्येक शुक्रवार को ग्राम चौपालों का आयोजन किया जा रहा है। "गांव की समस्यादृगांव में समाधान" की अवधारणा पर आधारित इन चौपालों के माध्यम से बड़ी संख्या में ग्रामीणों की व्यक्तिगत और सार्वजनिक समस्याओं का निराकरण उनके गांव में ही किया जा रहा है। डबल इंजन सरकार की यह पहल प्रशासन को सीधे गांव और गरीबों तक पहुंचाने का माध्यम बन रही है।ग्राम चौपालों से जहां गांवों में चल रही विभिन्न विकास परियोजनाओं की जमीनी हकीकत सामने आ रही है, वहीं सामाजिक क्षेत्र की योजनाओं के क्रियान्वयन में भी तेजी आई है। उप मुख्यमंत्री के निर्देशों के अनुपालन में ठोस और प्रभावी कार्ययोजना के तहत चौपालों का आयोजन किया जा रहा है। चौपाल से पूर्व गांवों में सफाई व्यवस्था पर विशेष फोकस किया जा रहा है और ग्रामीणों को जागरूक करने के लिए व्यापक प्रचार–प्रसार भी किया जा रहा है। इन चौपालों में केवल व्यक्तिगत ही नहीं, बल्कि सामुदायिक और सार्वजनिक समस्याओं का भी मौके पर समाधान किया जा रहा है।ग्राम्य विकास विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार बीते शुक्रवार को प्रदेश की 1326 ग्राम पंचायतों में ग्राम चौपालों का आयोजन किया गया, जिनमें 3295 प्रकरणों का निस्तारण पंचायत स्तर पर ही कर दिया गया। इन चौपालों में 3295 ब्लॉक स्तरीय अधिकारी एवं कर्मचारी तथा 5599 ग्राम स्तरीय कर्मचारी मौजूद रहे। कार्यक्रमों में 64 हजार से अधिक ग्रामीणों ने सहभागिता की और अपनी समस्याएं सीधे अधिकारियों के समक्ष रखीं।विभागीय आंकड़ों के अनुसार अब तक प्रदेश में एक लाख 80 हजार से अधिक ग्राम चौपालों का आयोजन किया जा चुका है, जिनके माध्यम से छह लाख से अधिक समस्याओं और प्रकरणों का समाधान किया गया है। उप मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि ग्राम चौपालों का आयोजन नियमित और विधिवत रूप से जारी रखा जाए, ताकि शासन की योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंच सके और गांवों के समग्र विकास को नई गति मिल सके।

माघ मेला-2026 में कला और अध्यात्म का महासंगम, प्रयागराज में 30 जनवरी तक गूंजेंगी भव्य सांस्कृतिक प्रस्तुतियाँ

प्रयागराज,लखनऊ(संवाददाता) । संस्कृति विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार के अंतर्गत संस्कृति निदेशालय के अधीन कार्यरत स्वायत्तशासी संस्थाओं द्वारा माघ मेलादृ2026 के पावन अवसर पर 03 जनवरी से 30 जनवरी, 2026 तक प्रयागराज में भव्य सांस्कृतिक प्रस्तुतियों का आयोजन किया जा रहा है। यह आयोजन भारतीय संस्कृति, सनातन परंपरा और आध्यात्मिक चेतना के त्रिवेणी संगम का सजीव प्रतीक बनेगा, जहां कला और अध्यात्म एक–दूसरे में विलीन होते दिखाई देंगे।पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि त्रिवेणी संगम की पुण्यभूमि प्रयागराज में आयोजित माघ मेला प्राचीन काल से तप, साधना, स्नान, दान और सत्संग की परंपरा का केंद्र रहा है। इसी आध्यात्मिक ऊर्जा से प्रेरित होकर आयोजित होने वाली सांस्कृतिक प्रस्तुतियाँ शास्त्रीय, लोक और भक्ति परंपराओं के माध्यम से भारतीय जीवन दर्शन और सांस्कृतिक मूल्यों को प्रभावी रूप से अभिव्यक्त करेंगी। संस्कृति विभाग द्वारा कला एवं साहित्य जगत से जुड़े ख्यातिलब्ध कलाकारों के चयन और मानदेय निर्धारण की प्रक्रिया के अंतर्गत विविध सांस्कृतिक कार्यक्रमों की श्रृंखला प्रस्तुत की जाएगी।इन प्रस्तुतियों में शास्त्रीय संगीत की ध्रुपद और खयाल विधाएं, वाद्य संगीत में सितार, सरोद, बाँसुरी, पंचनाद और वाद्यवृंद, शास्त्रीय नृत्य एवं नृत्य–नाटिकाओं में कथक और ओडिसी, लोकनृत्यों में ढेढिया, करमा, मयूर, फरुवाही, अवध लोकनृत्य, फूलों की होली और पाई डंडा जैसी रंगारंग प्रस्तुतियाँ शामिल होंगी। इसके साथ ही भजन, कबीर वाणी, सुंदरकांड, शंख वादन, शास्त्रीय व उप–शास्त्रीय गायन तथा देशभक्ति से ओतप्रोत कार्यक्रम भी दर्शकों को आध्यात्मिक अनुभूति से जोड़ेंगे।जयवीर सिंह ने कहा कि माघ मेला केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि भारतीय आत्मा की जीवंत अभिव्यक्ति है। संस्कृति निदेशालय द्वारा आयोजित ये सांस्कृतिक प्रस्तुतियाँ शास्त्रीय और लोक परंपराओं को आध्यात्मिक चेतना से जोड़ते हुए समाज में संस्कार, समरसता और सांस्कृतिक गौरव की भावना को सुदृढ़ करेंगी। प्रयागराज की पावन भूमि पर कला और अध्यात्म का यह संगम 'एक भारतदृश्रेष्ठ भारत' की भावना को और अधिक मजबूत करेगा।

मनरेगा बचाओ अभियान को लेकर कांग्रेस का एलान, ग्रामीण गरीबों की जीवनरेखा पर हमला नहीं होने देगी पार्टी

लखनऊ(संवाददाता)। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, मनरेगा को कांग्रेस ने केवल एक सरकारी योजना नहीं, बल्कि ग्रामीण भारत के करोड़ों गरीब परिवारों की जीवनरेखा बताया है। कांग्रेस का कहना है कि यह योजना भूख, बेरोजगारी और पलायन के खिलाफ एक मजबूत सुरक्षा कवच है, जिसने दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, महिलाओं और भूमिहीन मजदूरों को सम्मान के साथ काम करने का अधिकार दिया है।कांग्रेस ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार के सत्ता में आने के बाद मनरेगा अधिनियम में ऐसे बदलाव किए जा रहे हैं, जिनके जरिए इस योजना को कमजोर करने और धीरे–धीरे समाप्त करने का कुत्सित प्रयास किया जा रहा है। पार्टी ने स्पष्ट किया कि वह भाजपा सरकार को किसी भी स्थिति में यह मजदूर विरोधी बदलाव करने नहीं देगी और मनरेगा की मूल भावना और अधिकारों की रक्षा के लिए सड़क से संसद तक संघर्ष करेगी।इसी क्रम में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव एवं उत्तर प्रदेश प्रभारी अविनाश पाण्डेय के निर्देश पर तथा प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के अनुमोदन के उपरांत कांग्रेस वर्किंग कमेटी द्वारा निर्देशित "मनरेगा बचाओ अभियान" को उत्तर प्रदेश में और अधिक गति एवं मजबूती के साथ लागू करने का निर्णय लिया गया है। इस अभियान को प्रभावी बनाने के लिए प्रदेश के सभी जनपदों में जिला एवं शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षों के सहयोग से वरिष्ठ कांग्रेस कार्यकर्ताओं को अभियान का समन्वयक नामित किया गया है।कांग्रेस ने कहा कि ये समन्वयक जिला संगठन और जनपद के वरिष्ठ जनों के सहयोग से केंद्रीय नेतृत्व द्वारा निर्धारित कार्ययोजना को धरातल पर उतारेंगे।

गोमती नदी पर 180 मीटर लंबा पेडेस्ट्रियन ब्रिज बनेगा, लखनऊ को नई पहचान देगा

लखनऊ(संवाददाता)। गोमती नदी पर पेडेस्ट्रियन ब्रिज के निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। लगभग 54 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले इस 180 मीटर लंबे ब्रिज के लिए शासन ने मंजूरी दे दी है। परियोजना का निर्माण 18 महीने में पूरा होगा और इसके लिए पहली किश्त के तौर पर 18.90 करोड़ रुपये की धनराशि भी स्वीकृत कर दी गई है। यह ब्रिज 'मुस्कुराइए, आप लखनऊ में हैं' की थीम पर विकसित किया जाएगा और राजधानी को एक नई पहचान देगा।लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) के उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने बताया कि यह ब्रिज एडीसीपी ऑफिस के पास अहमदाबाद के अटल ब्रिज की तर्ज पर बनाया जाएगा और रिवर फ्रंट के दोनों किनारों को जोड़ेगा। ब्रिज की अनूठी डिजाइन के लिए आर्किटेक्ट डिजाइन प्रतियोगिता आयोजित की गई थी, जिसमें देश भर की लगभग 25 संस्थाओं ने भाग लिया। जूरी पैनल ने मुंबई की संस्था 'आरवैम्प स्टूडियो' की डिजाइन को चयनित किया।ब्रिज के निर्माण से गोमती नदी के दायें किनारे पर लोगों की आवाजाही बढ़ेगी और विकसित क्रिकेट स्टेडियम, विवाह स्थल, किड्स प्ले एरिया, एम्फीथिएटर, फ्लोटिंग रेस्टोरेंट और वॉटर स्पोर्ट्स जैसी गतिविधियों की उपयोगिता भी बढ़ेगी।उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने बताया कि ब्रिज की चौड़ाई 12 मीटर होगी। रैम्प और प्लेटफार्म मिलाकर इसकी कुल लंबाई 380 मीटर होगी। ब्रिज के स्ट्रक्चर को संभालने के लिए 13 पीयर्स बनाए जाएंगे, जबकि पुल के तल पर 30 मीटर और 40 मीटर चौड़े स्पैन प्लेट गर्डर्स लगाए जाएंगे, जहां लोग खड़े होकर नदी का नजारा देख सकेंगे। ब्रिज की किनारों की संरचना स्टील ट्यूबलर सेक्शन से की जाएगी।ब्रिज की सतह पर स्टाम्प कंक्रीटिंग, जीआरसी पैनल, ग्रेनाइट और एसीपी पैनल का कार्य किया जाएगा। इसके अलावा टेन्साइल स्ट्रक्चर से रूफिंग और स्ट्रीट लाइट्स, बोलार्ड लाइट्स एवं फ्लोर लाइट्स लगाई जाएंगी, जिससे रात में भी ब्रिज की सुंदरता और सुरक्षा सुनिश्चित होगी।उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने कहा कि परियोजना की कुल लागत लगभग 54 करोड़ रुपये है और शासन ने पहले चरण के लिए 18.90 करोड़ रुपये की वित्तीय स्वीकृति प्रदान कर दी है। यह ब्रिज न केवल लखनऊ के रिवर फ्रंट को और आकर्षक बनाएगा, बल्कि नागरिकों और पर्यटकों के लिए सुविधाजनक और मनोरंजक स्थल भी बनेगा।

नागरिक सुरक्षा वार्डेन क्षमता निर्माण प्रशिक्षण कार्यक्रम का गरिमामय समापन

लखनऊ(संवाददाता)। इन्दिरा गांधी प्रतिष्ठान, लखनऊ स्थित मून हॉल में संचालित नागरिक सुरक्षा संगठन के वार्डेन क्षमता निर्माण प्रशिक्षण कार्यक्रम का समापन समारोह गरिमामय वातावरण में सम्पन्न हुआ।

कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक डी.के. ठाकुर (आईपीएस) मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे।समारोह का शुभारम्भ मुख्य अतिथि द्वारा दीप प्रज्वलन कर किया गया। इसके उपरान्त नागरिक सुरक्षा संगठन के चीफ वार्डेन अमरनाथ मिश्र द्वारा पुलिस महानिदेशक डी.के. ठाकुर को अंगवस्त्र, पुष्पगुच्छ एवं प्रतीक चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के दौरान प्रशिक्षण पूर्ण करने वाले सभी वार्डेनों को प्रमाण–पत्र वितरित किए गए।समापन सत्र को सम्बोधित करते हुए पुलिस महानिदेशक डी.के. ठाकुर ने कहा कि आपदा प्रबंधन, आपातकालीन परिस्थितियों तथा जन–सुरक्षा के क्षेत्र में प्रशिक्षित नागरिक सुरक्षा वार्डेनों की भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण है। उन्होंने स्वयंसेवकों को अनुशासन, सेवा–भाव एवं निरन्तर प्रशिक्षण के माध्यम से समाज सेवा हेतु सदैव तत्पर रहने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले सभी वार्डेनों को बधाई देते हुए कहा कि इस प्रकार के क्षमता निर्माण कार्यक्रम स्वयंसेवकों के कौशल विकास के साथ–साथ नागरिक सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाने में सहायक सिद्ध होते हैं।कार्यक्रम के अंत में चीफ वार्डेन अमरनाथ मिश्र ने जानकारी देते हुए बताया कि यह प्रशिक्षण कार्यक्रम कुल चार सत्रों में आयोजित किया गया, जिसमें प्रत्येक सत्र की अवधि सात दिवस की रही। प्रत्येक सत्र में 90 प्रशिक्षार्थियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया। इस प्रकार कुल 360 वार्डेनों ने प्रशिक्षण प्राप्त कर प्रमाण–पत्र प्राप्त किए। उन्होंने सभी अतिथियों, प्रशिक्षकों एवं प्रतिभागियों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि भविष्य में भी ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन निरन्तर किया जाएगा, जिससे नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवकों को और अधिक सक्षम एवं प्रशिक्षित बनाया जा सके।समारोह में स्टाफ ऑफिसर टू चीफ वार्डेन ऋतुराज रस्तोगी, सुनील शुक्ला, नफीस अहमद, डॉ. दिनेश माथुर, सुनील तिवारी, अरविन्द मिश्रा, माजिद अली, रामगोपाल एश्वर्य, ज्योति खरे, अय्याज सिद्दीकी, सुनील कुमार यादव, राजेन्द्र श्रीवास्तव, सुनील करन चंदानी, गुफरान, उपनियंत्रक रविन्द्र कुमार, एडीसी मनोज वर्मा, ऋषि कुमार, मुकेश, ममता रानी, रेखा सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे।

उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी और सामाजिक अन्याय के खिलाफ आम आदमी पार्टी की निर्णायक पदयात्रा, 16 से 22 जनवरी तक 'रोजगार दो,सामाजिक न्याय दो' अभियान

लखनऊ(संवाददाता)। आम आदमी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी, पेपर लीक, भर्ती प्रक्रियाओं में घोटालों, आरक्षण के संवैधानिक अधिकारों के हनन और बढ़ते सामाजिक भेदभाव के खिलाफ निर्णायक संघर्ष का एलान किया है। आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश की प्रभारी एवं राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने बताया कि पार्टी अपने तीसरे चरण की 'रोजगार दोदृ सामाजिक न्याय दो' पदयात्रा 16 जनवरी से 22 जनवरी तक आयोजित करेगी। यह पदयात्रा मिर्जापुर के शहीद उद्यान से प्रारम्भ होकर काशीदृवाराणसी के सारनाथ तक लगभग 90 से 100 किलोमीटर के मार्ग पर निकाली जाएगी।प्रेस वार्ता को सम्बोधित करते हुए संजय सिंह ने कहा कि आम आदमी पार्टी का स्पष्ट उद्देश्य युवाओं को नौकरी दिलाना, वंचित वर्गों को संवैधानिक न्याय दिलाना और सरकार को जनता के प्रति जवाबदेह बनाना है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में रोजगार के नाम पर एक संगठित खेल चल रहा है, जिसमें कभी पेपर लीक, कभी हाईकोर्ट से स्टे और कभी सुप्रीम कोर्ट में सरकार की अपील के चलते भर्तियां वर्षों तक लटकाई जा रही हैं। इसका परिणाम यह है कि नौजवान हाथ में फाइल और आंखों में सपने लिए दर–दर भटकने को मजबूर है। उन्होंने आरोप लगाया कि लेखपाल, दरोगा, सिपाही, पीसीएस–जे जैसी प्रमुख परीक्षाओं में बार–बार गड़बड़ियां कराकर युवाओं का भविष्य चौपट किया गया है।संजय सिंह ने भर्ती प्रक्रियाओं में ओबीसी, एससी और एसटी वर्ग के संवैधानिक आरक्षण को सुनियोजित तरीके से कमजोर करने का आरोप लगाते हुए कहा कि 69 हजार शिक्षक भर्ती हो, बांदा विश्वविद्यालय, लखीमपुर कोऑपरेटिव बैंक या पशुधन विभागकृलगभग हर जगह आरक्षण के अधिकार पर डाका डाला गया। उन्होंने कहा कि आरक्षण किसी राजनीतिक दल की देन नहीं, बल्कि संविधान का अधिकार है और इसी अधिकार को लगातार कुचला जा रहा है। उनके अनुसार सामाजिक न्याय का मुद्दा इसलिए केंद्रीय है क्योंकि नौकरी के साथ–साथ सम्मान भी छीना जा रहा है।

उन्होंने प्रदेश में बढ़ती सामाजिक अपमान की घटनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि कहीं किसी बुजुर्ग को अपमानित किया जाता है, कहीं किसी कथावाचक की चुटिया इसलिए काट दी जाती है क्योंकि वह पिछड़ी जाति से आता है, तो कहीं एक सीआरपीएफ के जवान को घोड़ी पर चढ़ने से रोका जाता है। उन्होंने कहा कि यह सब उत्तर प्रदेश की सच्चाई बन चुकी है और इसी तस्वीर को बदलने के लिए यह पदयात्रा निकाली जा रही है।संजय सिंह ने बताया कि बेरोजगारी से त्रस्त बुनकर समाज, बुलडोजर कार्रवाई से प्रभावित रेहड़ीदृपटरी वाले, आशा बहुएं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, रोजगार सेवक, शिक्षामित्र, नियमितीकरण और पेंशन की मांग कर रहे कर्मचारीकृहर उस वर्ग की आवाज यह यात्रा बनेगी जो अपने हक के लिए संघर्ष कर रहा है।

प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में सावित्रीबाई फुले की जयंती मनाई गई, शिक्षा और नारी सशक्तिकरण के संघर्ष को किया गया नमन

लखनऊ(संवाददाता)। भारत की प्रथम महिला शिक्षिका, महान समाज सुधारक एवं नारी सशक्तिकरण की अग्रदूत सावित्रीबाई फुले की जयंती आज प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में श्रद्धा और सम्मान के साथ मनाई गई। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निवर्तमान प्रदेश उपाध्यक्ष दिनेश कुमार सिंह ने सावित्रीबाई फुले के चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित किए।इस अवसर पर दिनेश कुमार सिंह ने कहा कि सावित्रीबाई फुले ने उस दौर में शिक्षा की अलख जगाई, जब महिलाओं और दलितों को पढ़ने से वंचित रखा जाता था। उन्होंने सामाजिक कुरीतियों, जातिगत भेदभाव और लैंगिक असमानता के विरुद्ध संघर्ष करते हुए शिक्षा को सामाजिक परिवर्तन का सबसे सशक्त माध्यम बनाया। सावित्रीबाई फुले का जीवन संघर्ष, साहस और समर्पण की प्रेरणादायी मिसाल है, जिसने आने वाली पीढ़ियों को समानता और अधिकारों की लड़ाई लड़ने की दिशा दी।उन्होंने कहा कि सावित्रीबाई फुले का योगदान केवल शिक्षा तक सीमित नहीं था, बल्कि उन्होंने महिला अधिकारों, सामाजिक न्याय और मानव गरिमा की स्थापना के लिए आजीवन संघर्ष किया।

उनका जीवन आज भी समाज के वंचित वर्गों को आगे बढ़ने और अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाने की प्रेरणा देता है।कार्यक्रम में वरिष्ठ कांग्रेस नेता अनीस अंसारी, शिक्षक प्रकोष्ठ के चेयरमैन अमित राय सहित उपस्थित कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने भी सावित्रीबाई फुले के चित्र पर श्रद्धासुमन अर्पित किए और उनके विचारों को आत्मसात करने का संकल्प लिया।

पर्व-त्योहारों और माघ मेला को लेकर मुख्यमंत्री ने की उच्चस्तरीय समीक्षा, सुरक्षा व सुविधाओं में लापरवाही बर्दाश्त नहीं

लखनऊ(संवाददाता)। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार सायं आगामी पर्व–त्योहारों तथा माघ मेला के दृष्टिगत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबंधित जनपदों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ उच्चस्तरीय सुरक्षा एवं व्यवस्थागत समीक्षा बैठक की। बैठक में मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा, सुविधा और आयोजन की सुचारू व्यवस्था राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है तथा इसमें किसी भी स्तर पर लापरवाही स्वीकार्य नहीं होगी।मुख्यमंत्री ने प्रयागराज, वाराणसी, अयोध्या, चित्रकूट, हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर, मथुरा–वृंदावन, फर्रुखाबाद, शाहजहांपुर सहित माघ मेला से जुड़े सभी प्रमुख जनपदों के अधिकारियों को निर्देश दिए कि श्रद्धालुओं के आवागमन की समुचित व्यवस्था की जाए। घाटों और मंदिर परिसरों की नियमित स्वच्छता, निर्बाध विद्युत आपूर्ति, महिलाओं के लिए चेंजिंग रूम, प्रभावी कंट्रोल रूम, भीड़ प्रबंधन तथा मेला क्षेत्र में प्रवेश और निकास की सुगम व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि किसी भी स्थिति में अराजकता को बढ़ावा न मिले और सभी श्रद्धालु सुरक्षित वातावरण में स्नान व पूजा–अर्चना कर सकें।प्रयागराज में पौष पूर्णिमा के अवसर पर अनुमानित 15 से 25 लाख श्रद्धालुओं के आगमन को देखते हुए मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य सेवाओं को विशेष रूप से सुदृढ़ करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अस्पतालों में पर्याप्त व्यवस्था, मेडिकल स्टाफ की तैनाती, एम्बुलेंस, स्वच्छ शौचालय, पेयजल तथा महिला सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। साथ ही घाटों पर गोताखोरों की पर्याप्त तैनाती रहे, ताकि किसी भी आपात स्थिति से तत्काल निपटा जा सके।महिलाओं की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता बताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि मेला क्षेत्रों और सार्वजनिक स्थलों पर संदिग्ध एवं अराजक तत्वों की पहचान कर उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाए। किसी भी महिला श्रद्धालु को असुविधा या भय का सामना न करना पड़े, यह प्रशासन सुनिश्चित करे।नगर विकास एवं पंचायती राज विभाग को निर्देश देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी जनपदों में स्वच्छता अभियान को तेज किया जाए। विशेष रूप से मलिन बस्तियों में व्यापक साफ–सफाई और शुद्ध पेयजल की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए, जिससे संक्रामक रोगों की संभावना को रोका जा सके। उन्होंने कहा कि स्वच्छ और स्वस्थ वातावरण प्रत्येक नागरिक का अधिकार है।भीषण शीतलहर को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री ने रैन बसेरों की पर्याप्त व्यवस्था, अलाव जलाने तथा रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और सार्वजनिक स्थलों पर प्रकाश व्यवस्था सुदृढ़ करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि कोई भी व्यक्ति खुले आसमान के नीचे सोने के लिए विवश न हो। पुलिस पेट्रोलिंग बढ़ाई जाए और जरूरतमंदों को रैन बसेरों तक पहुंचाया जाए।मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि सभी वरिष्ठ अधिकारी रात्रि में ही मेला स्थलों का निरीक्षण करें और अधीनस्थ अधिकारियों व कर्मचारियों को सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दें।

नदी में तेज बहाव या अधिक गहराई की स्थिति में बैरिकेडिंग लगाकर सुरक्षा पुख्ता की जाए। किसी भी नाविक द्वारा श्रद्धालुओं से मनमाना शुल्क वसूलने की अनुमति नहीं होगी।उन्होंने तीर्थ स्थलों और अन्य महत्वपूर्ण स्थानों पर नाव संचालन, होटल एवं अन्य सेवाओं में मनमानी वसूली पर सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि वरिष्ठ अधिकारी स्वयं फील्ड पर उतरकर यह सुनिश्चित करें कि किसी प्रकार की अवैध वसूली न हो।

रात्रिकालीन अभियान में Arto का ओवरलोड और ओवरहाइट वाहनों पर शिकंजा

लखीमपुर खीरी में परिवहन विभाग ने की 12 वाहन सीज और 12 चालान की कार्रवाई चार लाख रुपए प्रशमन शुल्क वसूला

(सुनील शर्मा)

लखीमपुर खीरी, । सड़क सुरक्षा माह के तीसरे दिन जिले की सड़कों पर सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए परिवहन विभाग ने ओवरलोड और गन्ना परिवहन में प्रयुक्त ओवरहाइट वाहनों पर शिकंजा कसा। एआरटीओ शशि भूषण पांडे और पीटीओ डॉ0 कौशलेंद्र अलग–अलग मार्गों पर मुस्तैद दिखाई दिए। गत दिवस विभाग ने कुल 12 चालान काटे और छः ओवरलोड एवं ओवरहाइट वाहनों को सीज किया। वहीं छह अन्य मामलों में भी वाहनों के सीजर की कार्रवाई की गई। शुक्रवार की रात्रि एवं शनिवार दोपहर में विभागीय अफसरों ने विभिन्न मार्गों पर छः ओवरलोड वाहनों को सीज किया और 12 वाहनों का चालान किया। एआरटीओ शशि भूषण पांडे ने कहा कि यह अभियान सड़क सुरक्षा माह के दृष्टिगत सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने, दुर्घटनाओं को रोकने और नियमों के उल्लंघन पर कड़ी कार्रवाई करने के लिए चलाया गया है। उन्होंने चेतावनी दी है कि भविष्य में ओवरलोडिंग और ओवरहाइट वाहनों पर कोई ढील नहीं बरती जाएगी। सड़क पर सुरक्षित परिवहन और आम जनता की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह अभियान निरंतर जारी रहेगा। विभाग ने आम नागरिकों से भी अपील की है कि वाहन चलाते समय नियमों का पालन करें और ओवरलोडिंग से बचें।

प्रधानमंत्री 4 जनवरी को वाराणसी में 72वें राष्ट्रीय वॉलीबॉल टूर्नामेंट का उद्घाटन करेंगे

विभिन्न राज्यों और संस्थानों का प्रतिनिधित्व करने वाली 58 टीमों के हिस्से के रूप में 1,000 से अधिक खिलाड़ी भाग लेंगे प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी

4 जनवरी, 2026 को दोपहर 12 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 72वें राष्ट्रीय वॉलीबॉल टूर्नामेंट का उद्घाटन करेंगे। उद्घाटन समारोह डॉ. संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम, वाराणसी में आयोजित किया जाएगा। 4 से 11 जनवरी तक आयोजित होने वाले इस टूर्नामेंट में पूरे भारत से विभिन्न राज्यों और संस्थानों का प्रतिनिधित्व करने वाली 58 टीमों के हिस्से के रूप में 1,000 से अधिक खिलाड़ी भाग लेंगे। टूर्नामेंट में भारतीय वॉलीबॉल में प्रतिस्पर्धा, खेल भावना और प्रतिभा के उच्च मानकों का प्रदर्शन होने की आशा है। वाराणसी में 72वीं राष्ट्रीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन शहर में खेल अवसंरचना को सुदृढ़ करने और एथलेटिक के विकास को बढ़ावा देने को दर्शाता है। यह आयोजन प्रमुख राष्ट्रीय आयोजनों के केंद्र के रूप में वाराणसी की पहचान को और सशक्त करता है तथा सांस्कृतिक और खेल गतिविधियों की मेजबानी में शहर की बढ़ती भूमिका के अनुरूप है।

परिवार परामर्श केन्द्र में काउन्सलरों के सहयोग से महिला उत्पीडन के 07 मामलों का हुआ सुलह से निस्तारण पति पत्नी हुए विदा

महिला हेल्प लाइन नम्बर व योजनाओं के बारे में किया जागरूक

लखीमपुर खीरी। उत्तर प्रदेश शासन की मंशा के अनुरूप जनपद खीरी के पुलिस अधीक्षक संकल्प शर्मा के निर्देशन में पति पत्नी व परिवारिक विवाद में सुलह समझौते से शिकायतों का निस्तारण कराया जा रहा है इसी क्रम में पुलिस लाइन स्थित ष्परिवार परामर्श केंद्रष में काउंसलरो के सहयोग से सुलह समझौते का अभियान निरन्तर चलाया जा रहा है ! बताते चलें कि जनपद मुख्यालय पर पुलिस अधीक्षक संकल्प शर्मा के दिशा निर्देशन में परिवार परामर्श केन्द्र में काउंसलर श्रीमती नीति गुप्ता, कय्यूम जरवानी, सुश्री क्षमा टंडन, महिला आरक्षी निकिता राठौर, मेहा सिंह के द्वारा दहेज उत्पीड़न, घरेलू हिंसा के उत्पीड़न, साझी गृहस्थी में निवास को लेकर उत्पन्न होने वाली समस्याओं मामलों में बैठक कर परिवारों के विघटन को रोकने का काम परामर्श के द्वारा किया जाता है , इसी क्रम में काउन्सलरों की उपस्थिति में 14 प्रार्थना पत्रों में काउंसलिंग की गई

जिसमें 07 जोड़े पति–पत्नी साथ रहने के लिए सहमत हुए ,03 मामले ऐसे थे जिनमें पति–पत्नी में अत्यधिक मनमुटाव था उन्हें सोचने का समय दिया गया है, व माननीय न्यायालय में 04 मामले लम्बित होने के कारण सुलह नहीं हो सकी है,मिशन शक्ति के अन्तर्गत इस अवसर पर उपस्थित महिलाओं और उनके साथ आये पारिवारिक जनो को हेल्प लाइन नम्बर व महिलाओं के लिए चलाई जा रही योजनाओं के बारे में जागरूक किया गया है।

शिशु वाटिका में मनाई गई भारत की प्रथम शिक्षिका सावित्रीबाई फुले की जयंती

लखीमपुर खीरी।विद्या भारती विद्यालय सनातन धर्म सरस्वती शिशु वाटिका लखीमपुर खीरी में आज आज वंदना सभा में भारत की प्रथम शिक्षिका आदरणीया सावित्रीबाई फुले की जयंती दीप प्रज्जवलन एवं पुष्पार्चन कर मनाई गई। कार्यक्रम की संयोजिका सुश्री अंशिका तिवारी ने उनके जीवन पर प्रकाश डालते हुए बताया कि उनका जन्म 3 जनवरी 1831 को हुआ था इनके पिता का नाम खन्दोजी नैवेसे और माता का नाम लक्ष्मीबाई था। सावित्रीबाई फुले का विवाह 1841में महात्मा ज्योतिराव फुले के साथ हुआ। सावित्रीबाई फुले भारत के पहले बालिका विद्यालय की पहली प्रिंसिपल (भारत की प्रथम महिला शिक्षिका) और पहले किसान स्कूल की संस्थापक थी उनको महिलाओं और अनाथ दीन दुखी, गरीबों लोगों को शिक्षित करने के प्रयासों के लिए जाना जाता है। ज्योति राव, जो बाद में ज्योतिबा के नाम से जाने गए ज्योति बाई सावित्रीबाई के संरक्षक, गुरु और समर्थक थे ।सावित्रीबाई ने अपने जीवन को एक मिशन की तरह जिया जिसका उद्देश्य था विधवा विवाह करवाना, छुआछूत मिटाना, महिलाओं की मुक्ति और महिलाओं को शिक्षित बनाना। कीचड़ पर पत्थर फेंक कर रोका गया घर से निकाला,पर स्त्री शिक्षा की ज्योत जलायें रखी साबित्री बाई फुले ने ।वे एक कवियत्री भी थी उन्हें मराठी की आदिकवित्री के रूप में जाना जाता था। विद्यालय की संचालिका श्रीमती हीरा सिंह ने बताया कि उन्होंने बहुत सी सामाजिक मुश्किलों का सामना किया जब वे स्कूल जाती थी तो उनका विरोध होता था। सावित्रीबाई फुले पूरे देश की नायिका रही हर बिरादरी हर धर्म के लिए उन्होंने काम किया । शिक्षा के क्षेत्र में सावित्रीबाई फुले ने बहुत बड़ा योगदान किया। 5 सितंबर 1848 में पुणे में अपने पति के साथ मिलकर विभिन्न जातियों की नौ छात्राओं के साथ उन्होंने महिलाओं के लिए एक विद्यालय की स्थापना की। एक वर्ष में सावित्रीबाई और महात्माफुले पांच नए विद्यालय खोलने में सफल हुए। तत्काल उनके कार्य को देख कर सरकार ने उनको सम्मानित भी किया ।एक महिला प्रिंसिपल के लिए सन 1848 में बालिका विद्यालय चलाना कितना मुश्किल रहा होगा, इसकी कल्पना शायद आज भी नहीं की जा सकती ।लड़कियों की शिक्षा पर उसे समय सामाजिक पाबंदी थी। सावित्रीबाई फुले उसे दौर में न सिर्फ खुद पढ़ी ,बल्कि दूसरी लड़कियों के पढ़ने का इंतजाम भी किया। उनका निधन 10 मार्च 1897 को प्लग के कारण सावित्रीबाई फुले का निधन हो गया प्लेग महामारी में सावित्रीबाई मरीजों की सेवा करती थी। प्लेग से प्रभावित बच्चों की सेवा करने के कारण उनको भी यह बीमारी लग गई इसी कारण उनकी मृत्यु हो गई। सावित्रीबाई फुले पर साहित्य प्रकाशित किया गया। इस अवसर पर समस्त शिक्षिका बहिनें एवं कर्मचारी भैया बहन उपस्थित रहे।

मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना से 27 लाख बेटियों को संबल, योगी सरकार ने 647 करोड़ रुपये किए व्यय

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में बालिकाओं के कल्याण और सशक्तिकरण के लिए योगी आदित्यनाथ सरकार विभिन्न योजनाओं के माध्यम से निरंतर प्रभावी प्रयास कर रही है। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के जरिए सरकार ने यह स्पष्ट संदेश दिया है कि बेटियां बोझ नहीं, बल्कि समाज की सशक्त आधारशिला हैं। इस योजना के माध्यम से अब तक लगभग 27 लाख बालिकाओं को लाभ पहुंचाया जा चुका है, जिससे उनका भविष्य सुरक्षित और सशक्त हो रहा है।योजना का मुख्य उद्देश्य प्रदेश में लैंगिक समानता को बढ़ावा देना, कन्या भ्रूण हत्या पर रोक लगाना तथा बालिकाओं के जन्म के प्रति समाज में सकारात्मक सोच विकसित करना है। आंकड़ों के अनुसार, योजना के तहत अब तक कुल 647.21 करोड़ रुपये की धनराशि व्यय की जा चुकी है। यह दर्शाता है कि यह योजना केवल कागजी घोषणा नहीं, बल्कि जमीनी स्तर पर प्रभावी ढंग से लागू की जा रही है।

राज्य सरकार ने योजना के लिए पर्याप्त बजट की व्यवस्था की है। चालू वित्तीय वर्ष में ही 3.28 लाख लाभार्थियों को 130.03 करोड़ रुपये की सहायता प्रदान की गई है। इससे स्पष्ट है कि योगी सरकार बालिकाओं के कल्याण को दीर्घकालिक नीति के रूप में आगे बढ़ा रही है। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना आज प्रदेश में बेटियों के सम्मान, सुरक्षा और शैक्षिक सशक्तिकरण की एक सशक्त पहचान बन चुकी है।

वर्ष 2019 में शुरू की गई इस योजना का लाभ उत्तर प्रदेश के मूल निवासी परिवारों की बालिकाओं को दिया जा रहा है। पात्रता के अनुसार परिवार की वार्षिक आय 3 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए तथा परिवार में अधिकतम दो बच्चे होने चाहिए। योजना का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि आर्थिक कारणों से किसी भी बालिका की शिक्षा या विकास बाधित न हो।

वित्तीय वर्ष 2024–25 में प्रदेश सरकार ने योजना के अंतर्गत दी जाने वाली कुल सहायता राशि को 15,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये कर दिया है। यह राशि छह चरणों में प्रदान की जाती है। जन्म के समय 5,000 रुपये, दो वर्ष की आयु पर टीकाकरण पूर्ण होने पर 2,000 रुपये, कक्षा 1 में प्रवेश पर 3,000 रुपये, कक्षा 6 में प्रवेश पर 3,000 रुपये, कक्षा 9 में प्रवेश पर 5,000 रुपये तथा कक्षा 10 या 12 की परीक्षा उत्तीर्ण कर डिप्लोमा, स्नातक अथवा उससे अधिक अवधि के डिग्री पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने पर 7,000 रुपये की सहायता दी जाती है।

यह योजना बालिकाओं को प्रत्येक शैक्षिक पड़ाव पर आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित कर रही है और समाज में बेटियों के प्रति सकारात्मक सोच को मजबूत करने में अहम भूमिका निभा रही है।

पुलिस ने आधा दर्जन लोगों पर मामला दर्ज कर जांच की शुरू

लखीमपुर–खीरी। सदर कोतवाली सदर के अंतर्गत सेठ घाट चौकी क्षेत्र निघासन रोड पर स्थित नायरा पेट्रोल पंप के पास मारपीट। बताते चलें नायरा पेट्रोल पंप के पास बीती रात हुई मारपीट के मामले में पुलिस ने कार्रवाई की है। पुलिस ने इस संबंध में करीब आधा दर्जन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है।सेठ घाट चौकी प्रभारी संतोष शुक्ला ने आज 3 जनवरी 2026 को दोपहर करीब 2 बजे जानकारी देते हुए बताया कि निघासन रोड स्थित नायरा पेट्रोल पंप के सामने कुछ लोगों ने प्रकाश नगर निवासी मोहित चौरसिया पुत्र छोटेलाल चौरसिया के साथ मारपीट की थी। मारपीट के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। पीड़ित मोहित चौरसिया ने रात में ही मौखिक रूप से पुलिस को घटना की जानकारी दी थी। आज सुबह करीब 11 बजे पीड़ित ने पुलिस को लिखित तहरीर दी। इस तहरीर के आधार पर पुलिस ने तीन नामजद और कुछ अज्ञात सहित करीब आधा दर्जन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। सेठ घाट चौकी प्रभारी संतोष शुक्ला ने बताया कि पीड़ित को मेडिकल परीक्षण के लिए भेज दिया गया है। मामले की आगे की जांच जारी है।

कर्मों का फल तुरंत नहीं मिलता- पंडित राजेश दीक्षित

(आलोक मिश्र)

लखीमपुर खीरी। कर्मों का फल तुरंत नहीं मिलता ।यदि झूठ बोलते ही जीभ गल जाती, चोरी करते ही हाथ कट जाते तो मनुष्य दुष्कर्म न करता। ईश्वर के यहां देर हो सकती है पर अंधेर नहीं है।जो कर्म छोड़कर भाग्य पर

निर्भर रहता है उसकी दुर्दशा होती है। इसीलिए गीता में निष्काम कर्म की महत्ता प्रतिपादित की गई है।जो भगवान को समर्पित कर निष्काम कर्म करते हैं,वे कमल के पत्ते की भांति निर्लिप्त रहते हैं।जो जैसा कर्म करेगा वह वैसा ही फल पायेगा।शुभ,अशुभ कर्म के अनुसार ही ईश्वर फल देता है। सद्बुद्धि की प्राप्ति से ही मनुष्य काम,क्रोध,लोभ, मोह, अहंकार से बच सकता है।यही सब मनुष्य के महान शत्रु हैं और इनके वशीभूत होकर मनुष्य दुर्बुद्धि ग्रस्त होकर नीच काम करता है। उक्त विचार हैं श्री वेदमाता गायत्री प्रचार समिति के संस्थापक अध्यक्ष यज्ञाचार्य पं राजेश दीक्षित के जिन्होंने ग्राम कैमासुर सिद्ध बाबा स्थान पर गायत्री दीप महायज्ञ संपन्न कराते हुए कहे। पांच सौ इक्यावन दीपों को प्रज्वलित कर दीप महायज्ञ के साथ महायज्ञ का समापन किया गया।महायज्ञ समापन पर भंडारे का आयोजन किया गया।

पीएम पर टिप्पणी मामले में लोक गायिका नेहा सिंह राठौर हिरासत में, हजरतगंज थाने पहुंची थीं बयान दर्ज कराने

लखनऊ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कथित अभद्र टिप्पणी के मामले में लोक गायिका नेहा सिंह राठौर को शनिवार को हजरतगंज पुलिस ने हिरासत में ले लिया। नेहा सिंह राठौर पुलिस के नोटिस के बाद खुद हजरतगंज कोतवाली बयान दर्ज कराने पहुंची थीं, जहां आवश्यक कानूनी प्रक्रिया के तहत पुलिस ने उन्हें हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की।

पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, नेहा सिंह राठौर के खिलाफ सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर की गई टिप्पणियों के संबंध में हजरतगंज थाने में पहले से मुकदमा दर्ज है। इसी मामले में लखनऊ पुलिस ने उन्हें नोटिस जारी किया था। बताया जा रहा है कि नेहा सिंह राठौर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर आपत्तिजनक और अभद्र टिप्पणी की थी। शिकायत मिलने के बाद हजरतगंज कोतवाली में उनके खिलाफ विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया गया था। पुलिस का कहना है कि मामला संवेदनशील है और जांच जारी है। पुलिस का कहना है कि नेहा सिंह राठौर को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है और आगे की कार्रवाई जांच के तथ्यों के आधार पर की जाएगी। फिलहाल पुलिस पूरे मामले में कानूनी प्रक्रिया का पालन कर रही है। गौरतलब है कि नेहा सिंह राठौर इससे पहले भी अपने गीतों और सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर विवादों में रही हैं। उनके खिलाफ अलग–अलग स्थानों पर शिकायतें दर्ज होने की बात भी सामने आ चुकी है।

बिजली कर्मचारियों की हड़ताल

कलेक्ट्रेट पावर हाउस पर ठप हुआ बिल जमा करने का काम

लखीमपुर खीरी। एक बिजली कर्मचारी की मौत के बाद कर्मचारियों ने कार्य बहिष्कार शुरू कर दिया है। इस हड़ताल के कारण कलेक्ट्रेट स्थित पावर हाउस पर बिजली बिल जमा करने का काम पूरी तरह ठप हो गया है, जिससे उपभोक्ताओं को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।शनिवार को दोपहर करीब 12 बजे शहर के इमली चौराहा निवासी विनोद कुमार बिजली बिल जमा करने पावर हाउस पहुंचे। उन्हें हड़ताल की जानकारी नहीं थी, जिसके कारण वे बिना बिल जमा किए ही वापस लौट गए। इसी तरह एक अन्य महिला भी अपनी पुत्री के साथ बिल जमा करने आई थी, लेकिन उसका बिल भी जमा नहीं हो सका।कर्मचारियों का यह कार्य बहिष्कार गढ़ी पावर हाउस पर तैनात टीजी–2 कर्मचारी रामगोपाल राणा की मौत के बाद शुरू हुआ है। कर्मचारियों का आरोप है कि रामगोपाल राणा की मौत के बाद उचित कार्रवाई नहीं की जा रही है जिससे वे नाराज हैं।

पीएलआई के लिए घर-घर सम्पर्क करें डाक कर्मचारी : हरे कृष्ण यादव

-मण्डल में एक साथ पीएलआई का 7 जनवरी को महाअभियान

अयोध्या। आगामी 7 जनवरी को डाक जीवन बीमा का विशेष महाअभियान की सफलता के लिए मण्डल के प्रवर अधीक्षक डाकघर हरे कृष्ण यादव ने मिल्कीपुर, खंडासा, कुमारगंज, इनायतनगर, अछोरा, शाहगंज, हरिंगटनगंज, मजरुद्दीनपुर, बारुन, कुचेरा डाकघर के सैकड़ों शाखा पोस्टमास्टर एवं सहायक शाखा पोस्टमास्टर के साथ मिल्कीपुर व शाहगंज उपडाकघर में व्यवसायिक समीक्षा बैठक किया । इस दौरान मण्डल के प्रवर अधीक्षक डाकघर हरे कृष्ण यादव ने कहा 7 जनवरी को मण्डल के सभी डाकघरों में एक साथ डाक जीवन बीमा का महाअभियान चलाया जाएगा । जिसके लिए आज से ही शाखा पोस्टमास्टर व सहायक पोस्टमास्टर अपने क्षेत्र के गांव में घर घर सम्पर्क करें और उन्हें योजनाओं से रुबरु कराकर भारत सरकार की अतिमहत्वाकांक्षी डाक जीवन बीमा योजना से जोड़ें । जिसमें डाक कर्मी अपने क्षेत्र के स्नातक डिग्री धारक, अध्यापक, पुलिस कर्मी, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील के साथ साथ स्नातक डिग्री धारकों से सम्पर्क कर भारत सरकार के डाक जीवन बीमा योजना का लाभ दिलवाने के लिए खूबियों से रूबरू करवाते हुए बीमा पॉलिसी करने का लक्ष्य होगा । इस दौरान प्रवर अधीक्षक श्री यादव ने कहा कि आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए प्राइमरी अध्यापक, पुलिस कर्मियों को पीएलआई में सबसे अधिक फायदा है डाक जीवन बीमा सुरक्षा कवच के साथ साथ धन संचय में भी लाभदायक है । उन्होंने यह भी बताया कि डाक जीवन बीमा में बिचौलियों की कोई जगह न होने के कारण किश्त कम है और भुगतान अधिक है साथ ही इसका प्रीमियम प्राइवेट बीमा कंपनियों से ही नहीं बल्कि सभी बीमा कम्पनियों से भी कम है । भारत सरकार की यह योजना सभी अध्यापकों एवं कर्मचारियों के लिए लाभदायक है इसका लाभ सभी को लेना चाहिए जिससे अल्प बचत के साथ आयकर में छूट भी है जो कर्मचारियों के भविष्य को सँवारने में अहम भूमिका निभायेगा । इस दौरान डाक निरीक्षक अभिषेक तिवारी ने बताया कि डाक जीवन बीमा पॉलिसी में किश्त कम अधिक भुगतान बोनस दिया जाता है। इससे पॉलिसी होल्डर को सीधा लाभ होता है । मुख्य विपणन अधिकारी सत्येन्द्र प्रताप सिंह ने बताया कि इस डाक जीवन बीमा योजना पर अन्य खर्चों को कम करके अधिक से अधिक भुगतान लाभ ग्राहक को दिया जाता है साथ साथ प्रत्येक माह किसी भी डाकघर में आसान किश्त जमा करने की सुविधा उपलब्ध कराया गया वार्षिक, अर्द्ध वार्षिक किश्तों को जमा करने पर छूट भी दिया जाता है । अन्य किसी भी बीमा कम्पनियों से कम किश्त एवं अधिक बोनस देय है। मतलब आपका पूरा पैसा आपके पॉलिसी में तथा आयकर में छुट व लोन की भी सुविधा उपलब्ध है । इस दौरान राघवेंद्र प्रताप सिंह, राहुल सिंह ओवरसियर घनश्याम पाण्डेय, शिवकांत सहित सैकड़ों ग्रामीण डाक सेवक मौजूद रहे ।

विद्युत कर्मी की मौत पर हंगामा

लखीमपुर खीरी गढ़ी पावर हाउस पर तैनात विद्युत टीजीटू कर्मचारी रामगोपाल राणा (45 वर्ष) की मौत हो गई। परिजनों ने अधीक्षण अभियंता की प्रताड़ना से मौत होने का आरोप लगाया और शव लेकर कोतवाली पहुंच गए। देखते देखते बड़ी संख्या में विद्युत कर्मचारी भी पहुंच गए। उन्होंने अधीक्षण अभियंता के खिलाफ नारेबाजी कर गिरफ्तारी की मांग की। मृतक के परिजनों ने कार्रवाई के लिए तहरीर दी। मृतक के बहनोई महादेव ने बताया कि अधीक्षण अभियंता ब्रह्मपाल कर्मचारियों को काफी परेशान करते हैं। शुक्रवार को उन्होंने देर रात तक बंद कमरे में बैठक कर रामगोपाल राणा को डांटा। देर रात वो घर पहुंचे और पूरी रात सो नहीं सके। सुबह तड़के पांच बजे उनकी हालत बिगड़ी। जिला अस्पताल ले जाते समय उनकी मौत हो गई।

कुढ़ा सादात में एक करोड़ की लागत से बनेगा अम्बेडकर पार्क

-रुदौली विधान सभा क्षेत्र को मिली अम्बेडकर पार्क की सौगात

अयोध्या। रूदौली विधायक राम चन्द्र यादव के द्वारा जनहित मे अति महत्वाकांक्षी परियोजना का प्रस्ताव उ.प्र. सरकार के पर्यटन विभाग को अयोध्या क्षेत्रान्तर्गत पर्यटकीय सुविधाओं के दृष्टिगत जनपद अयोध्या के विधान सभा क्षेत्र रुदौली के ग्राम कुढ़ासादात में अम्बेडकर पार्क के पर्यटन विकास कार्य किये जाने हेतु भेजा गया था । पर्यटन की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण परियोजना ग्राम कुढ़ासादात में अम्बेडकर पार्क के पर्यटन विकास कार्य किये जाने को वित्तीय वर्ष 2025—26 की प्रेषित परियोजनाओं की सूची में सम्मिलित किया गया है । निदेशालय स्तर पर विचार–विमर्श उपरान्त जनपद अयोध्या के विधान सभा क्षेत्र रुदौली के ग्राम कुढ़ासादात मे अम्बेडकर पार्क के विकास कार्य की परियोजना की लागत 100.00 लाख रूपये से कराये जाने की स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। श्री अयोध्या जी तीर्थ विकास परिषद ,अयोध्या के संयुक्त मुख्य कार्य पालक अधिकारी ने विधायक रामचन्द्र यादव को पत्र भेजकर अम्बेडकर पार्क मे पर्यटन विकास कार्य किये जाने की स्वीकृति सम्बन्धी जानकारी दी है। कुढ़ा सादात मे अम्बेडकर पार्क के पर्यटन विकास कार्य होने से रुदौली वासियों को अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त जन उपयोगी बहु उद्देश्यीय पार्क की सौगात होगी। रुदौली वासियों को बहु उद्देश्यीय अम्बेडकर पार्क के विकास कार्य किये जाने की स्वीकृति प्रदान होने पर क्षेत्र की जानते रुदौली विधायक रामचंद्र यादव की मांग और पैरवी पर बाबा साहब डॉ. बी.आर. अम्बेडकर के नाम पर बनने वाला यह महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट स्वीकृति मिलने पर पूर्व जिला पंचायत सदस्य डॉ.राम भवन रावत, गन्ना डायरेक्टर राजेश कुमार गौतम डॉ सत्तन लाल गौतम, अजय गौतम, पूर्व प्रधान संघ अध्यक्ष राम प्रेस यादव,किशोरी लाल यादव,पूर्व प्रधान अरविंद वर्मा ,संतोष कुमार रावत और मुन्ना लाल रावत ने रुदौली विधायक का स्वागत और अभिनंदन करने की बात कही।

मुलायम सिंह यादव की तस्वीर के साथ सपा कार्यकर्ता ने संगम में लगाई डुबकी

प्रयागराज। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज माघ मेले में सपा कार्यकर्ता ने आज स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव की तस्वीर के साथ संगम में पावन डुबकी लगायी। सौरभ राम नामक कार्यकर्ता ने मुलायम सिंह यादव की तस्वीर के साथ खुद भी डुबकी लगाई ।

स्वात्वाधिकारी, प्रकाशक, मुद्रक व सम्पादक आरती पाण्डेय द्वारा सांई आफसेट प्रिन्टर्स, ४० वासुदेव भवन भातखण्डे संगीत महाविद्यालय के पीछे, कैसरबाग लखनऊ से छपवाकर एमआईजी २/३७६ रश्मिखांड शारदानगर आशियाना लखनऊ उ० प्र० से प्रकाशित।

सम्पादक
आरती पाण्डेय

ek-
9807059191- 9026560178

Email-
adbhutsamachar@gmail.com
adbhutsamachar@hotmail.com

सभी विवादों का न्यायक्षेत्र लखनऊ होगा।